**13.18 hrs.**

## ESTIMATES COMMITTEE

### REPORT OF SUB-COMMITTEE ON DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORY, HYDERABAD

**Mr. Speaker:** I have to inform the House that the Chairman of the Estimates Committee, Shri A. C. Guha, has under Clause (ix) (b) of Direction 101 of Directions by the Speaker presented me a report of the Sub-Committee of the Estimates Committee on the Defence Research and Development Laboratory, Hyderabad of the Ministry of Defence. The Sub-Committee at their sitting held on 16th March, 1966 approved the report. As in the view of the Sub-Committee the Report contains information of classified nature, the disclosure of which is likely to be prejudicial to national security, the Chairman has desired that the report may be treated as secret and has also requested me to forward the report to Goverr.ment. I have accordingly forwarded the report to the Minister of Defence with a request that the action taken thereon may, in due course, be intimated to the Chairman, Estimates Committee.

---

**13.19 hrs.**

## *RE*: STATEMENT ON FOOD POSITION IN WEST BENGAL

**Shri S. M. Banerjee** (Kanpur): What about the Minister's statement?

**Mr. Speaker:** Is the Minister going to make a statement on the food position in Bengal?

**The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri C. Subramaniam):** Perhaps I may be able to make a statement tomorrow.

**Mr. Speaker:** All right.

**Shri S. M. Banerjee:** Are all the reports secret?

**13.19½ hrs.**

## COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

### TWENTY-FIRST REPORT

**Shri D. N. Tiwary** (Gopalganj): I beg to present the Twenty-first Report of the Committee on Public Undertakings on Air India.

---

**13.20 hrs.**

## *DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

### MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING—*Contd.*

**Mr. Speaker:** The House will now resume discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Information and Broadcasting.

**Shri M. R. Masani** (Rajkot): Sir, we would like to know when the hon. Minister will be replying to the debate. (*Interruption*).

**Mr. Speaker:** Out of four hours, 50 minutes, have already been exhausted. Three hours and ten minutes remain. That means that we have to finish it at 4.30 How much time will the hon. Minister take?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur):** About 45 minutes.

**Mr. Speaker:** Then, at quarter to four, I shall call him. Now, Shri D. S. Chaudhuri.

**श्री चि० सि० चौधरी** (मथुरा): अध्यक्ष महोदय, गत शुक्रवार को सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मैंने माननीय मंत्री से निवेदन किया था कि ब्रज क्षेत्र, मथुरा में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना की जाय । मैंने यह भी निवेदन किया था कि वहां पर रेडियो स्टेशन खोलने की मांग केवल मेरी ही

*Moved with the recommendation of the President.

[श्री दि० सिं० चौधरी]

नहीं है बल्कि इस सम्बन्ध में हमारी लोक सभा के बहुत से माननीय सदस्यों ने भी लिख कर दिया है, बहुत सी संस्थाओं की यह मांग है और जनता की मांग है हमारे माननीय मंत्री जिन्होंने बृजभाषा की बहुत सेवा की है, भाषा के लिए बहुत कार्य किया है, मैं समझता हूं कि इसमें उनका सहयोग होगा और वहां मथुरा में रेडियो स्टेशन की स्थापना की जायेगी । मैं इसी दौरान के बीच में मथुरा गया था तो मुझे मालूम हुआ कि वहां की जनता में आम धारणा पैदा हो गई है कि वहां रेडियो स्टेशन खुलने वाला है क्योंकि वहां कुछ रेडियो स्टेशन खोलने सम्बन्धी जांच आदि हुई थी और रेडियो स्टेशन वहां पर कायम होने के बारे में वहां के स्थानीय अखबारों में निकल गया है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां एक रेडियो स्टेशन खोलने की घोषणा तुरन्त होनी चाहिए । मैं चाहता हूं कि जब मंत्री जी आज बहस का जवाब दें उसी वक्त इस की घोषणा कर दी जाय और मेरी समझ में इसकी घोषणा करने का इससे अच्छा व उपयुक्त अवसर दूसरा नहीं हो सकता है । मैं अन्य माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वे इस रेडियो स्टेशन की मांग में मेरे साथ सहयोग करें और ऐसा होने से बहुत ठीक रहेगा ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जोकि हमारे और देश के सामने है वह अन्न उत्पादन बढ़ाने की है । खाद्यान्न का उत्पादन हमारे देश के किसान भाई करते हैं अब उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को शिक्षित करने और सलाह देने आदि के जहां अनेकों कार्य किये जाते हैं मैं समझता हूं कि रेडियो स्टेशन के द्वारा और इस मंत्रालय के द्वारा बहुत कुछ उपयोगी कार्य किया जा सकता है लेकिन मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं और मुझे यह कहने के लिए क्षमा करेंगे कि जिस तरीके से किसानों की उपेक्षा और अनदेखी की जाती है, जिस तरीके से किसानों की अवहेलना अन्य सरकारी विभागों द्वारा की जाती है उसी प्रकार इसमें भी उनको विकास का उपयुक्त अवसर नहीं दिया जाता, उन के

13.23 hrs.

[SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

उत्थान व विकास आदि के कार्यक्रम रुक जाते हैं । अगर हम देखें कि कितना समय बोलने वालों को दिया जाता है उसमें कितना किसानों को, मैं यही कहूंगा कि इस मंत्रालय की तरफ से भी किसानों के प्रति बिलकुल उपेक्षा है । आज जब खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना एक राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है जब हम सब के सामने प्रश्न है कि हम उत्पादन बढ़ायें तो किसानों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । इसलिए भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि जहां किसानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए खून, पसीना एक करता है वहां उनके बच्चों ने लड़ाई लड़ी । किसानों के बच्चे भारी तादाद में सेना में शामिल होकर शत्रु से लड़े और देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी । उनके माता पिता, किसान लोग खेतों में काम करते हैं और जो कर्मचारी काम करते हैं या जो हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं और शत्रु से मोर्चा लेते हैं उन के लिए अगर वे घी दूध और अन्न पैदा न करें तो वह समस्या हल नहीं हो सकती है और काम ठीक नहीं बन सकता है । मैं इस से आगे कहता हूं कि हमारी जो सरकार बनी हुई है इस सरकार के बनाने में भी किसानों का प्रमुख रूप से हाथ है । अधिकतर वोट इस के लिए दिए हैं तो वह किसानों ने ही दिये है । जो किसान रक्षा करे, जो किसान उत्पादन बढ़ायें और जो किसान हमें वोट देकर शासन की कुर्सी पर बैठायें उन्हीं किसानों की आज उपेक्षा हो मैं समझता हूं कि इस से ज्यादा गलत बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस तरह के कार्य-क्रम रक्खें और ऐसे विशेषज्ञ रक्खें जिन्हें कि इस समस्या का व्यवहारिक ज्ञान हो, अभी जो व्यवस्था है वह ठीक और उपयुक्त व्यवस्था नहीं है । इसके लिए ऐसे व्यक्ति रक्खें जांय जिन को खेती का व्यवहारिक ज्ञान हो और वह व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर किसानों को उसकी शिक्षा दें कि किस तरह से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से अच्छी फसल हो सकती

है और किस तरीके से किसानों को जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिएं और जो साधन उन्हें प्राप्त होने चाहिएं वह सब उन्हें मिल सकते हैं। किसानों के साथ कैसी उपेक्षा आज बर्ती जा रही है वह मैं बतलाना चाहता हूं। अब होता यह है कि हर विभाग का कोई एक विशेषज्ञ होता है। अगर गाने की कोई बात हो तो उस गाने के विशेषज्ञ की राय ली जायगी अगर इंजीनियरिंग की बात हो तो इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ से बात की जायगी लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि जब कोई खेती की बात हो किसानों की बात हो किसान के सम्बन्ध में कोई नीति बनाई जाती है, उस सबन्ध में कोई योजना बनाई जाती है तो उस के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति लिये जाते हैं जिनको कि महज किताबी ज्ञान होता है, जिनको कि कालिज सम्बन्धी और दूसरे देशों का ज्ञान होता है लेकिन खेती का व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकारी कार्यक्रम जो किसानों के लिए रक्खा जाय उस कार्यक्रम को बनाने के लिए और उचित सलाह देने के लिए उन में भी व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ व्यक्ति रक्खे जायें। उन्हें खेती बाड़ी का अनुभव होना चाहिए। खाली यह बतलाने और लैक्चर देने से काम नहीं चलना वाला है कि अमरीका में खेती कैसे होती है, जापान और दूसरे देशों में खेती कैसे होती है बल्कि उन्हें यह बतलाने की जरूरत है कि वे यहां अपने देश की वर्तमान स्थिति में और साधनों को दृष्टि में रखते हुए कसे देश के अन्न का उत्पादन बढ़ा सकते है ? इस दिशा में रेडियो द्वारा भी उपयोगी सलाह किसानों को उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में अपने प्रोग्रामों द्वारा दी जा सकती है ऐसे व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के हेतु आल इंडिया रेडियो स्टेशन से किसानों को उनकी भाषा में उपयोगी सलाह दी जानी चाहिए।

मंत्रालय की रिपोर्ट में मैंने पढ़ा है कि बच्चों की शिक्षा के लिए आल इंडिया रेडियो प्रोग्राम देता है। यहां दिल्ली में बच्चों को शिक्षा देने सबन्धी कार्यक्रम आल इंडिया रेडियो स्टेशन से प्रसारित किये जाते हैं लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारे इतने बड़े देश में और जितनी उसकी विशाल जनसंख्या है उसके ग्रामीण क्षेत्र के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अब यहां दिल्ली में इस तरह के विद्यार्थियों को शिक्षा देने के कार्यक्रम रखने की क्या जरूरत है? यहां वैसे ही बड़े बड़े कालिज हैं, युनिवरसिटीज हैं, विशेष योग्यता और अनुभव प्राप्त अध्यापक और प्रोफेसर्स आदि हैं, जहां अन्य सभी प्रकार की शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं व साधन सुलभ हैं। अच्छी से अच्छी शिक्षा यहां विद्यार्थी लोग प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो द्वारा शिक्षा सम्बन्धी प्रोग्राम ऐसे स्थानों पर प्रसारित कराये जाने चाहिएं जहां कि ऐसे साधन व सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जहां प्राईमरी स्कूल्स हैं, गांव स्तर पर स्कूल्स हैं, जहां कि अध्यापक विशेष योग्यता वाले नहीं होते हैं। हर एक प्राईमरी स्कूल में अगर आप रेडियो की व्यवस्था कर सकें तो वह उपयोगी सिद्ध होगा। रेडियो स्टेशन द्वारा वहां की स्थानीय भाषा में यह शिक्षा प्रदान की जाय जिसे कि वह उसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। अब गांव के मास्टर जो कि थोड़ी तनख्वाह पाने वाले होते हैं वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते है जिनको बाहर का ज्ञान नहीं होता है वहां के लिए रेडियो द्वारा ऐसे शिक्षा सम्बन्धी विशेष प्रसारण कराये जाने चाहिएं ताकि वहां के लोगों को वह अच्छी और विशेष शिक्षा सुलभ हो सके जो कि उन्हें नहीं प्राप्त हो पाती है।

मैं तो यह भी निवेदन करूंगा कि यह मंत्रालय कैबिनेट में यह सवाल उठाये और शिक्षा मंत्रालय से बात करके वित्त मंत्रालय से अधिक रुपया प्राप्त करे और शिक्षा मंत्रालय और यह मंत्रालय अगर आपस में सहयोग करते हैं तो मेरी राय में शिक्षा के लिए जितना यह मंत्रालय उपयोगी कार्य कर सकता है उतना दूसरा नहीं कर सकता है। रेडियो से

[श्री दि० सिं० चौधरी]

इस तरह के शिक्षापद प्रोग्राम की व्यवस्था गांव के स्कूलों में करने से निश्चित रूप से गांव के विद्यार्थियों को लाभ होगा। मैं चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाय और इस महत्वपूर्ण विषय की उपेक्षा न की जाय।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से पुनः यह प्रार्थना करूंगा कि मैंने जो तीन बातें रक्खी हैं उन पर वे ध्यान दें। पहली मुख्य बात तो यह मैंने कही है कि बृज क्षेत्र में मथुरा में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने यह कही है कि किसानों की शिक्षा व उनके उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी कार्यक्रमों में ऐसे विशेषज्ञ रक्खे जांय जिनको कि महज किताबी ज्ञान न होकर व्यवहारिक ज्ञान खेती का हो। जिन्होंने कि दूसरे देशों से शिक्षा लेकर और उच्च व विशेष योग्यता खोज आदि कार्य करके पाई हो ऐसे लोग इसमें रक्खे जायें। तीसरी बात मैंने यह कही है कि गांवों में वहां के प्राईमरी स्तर के अध्यापकों को उच्च और विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए गांवों के प्राईमरी स्कूलों में रेडियो प्रसारण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनके लिए विशेष प्रकार के प्रोग्राम्स सुनाये जा सकें। दिल्ली में इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहां तो अच्छे अच्छे अध्यापक मिल सकते हैं, अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स मिल सकते हैं इसलिए यह रेडियो द्वारा शिक्षा सम्बन्धी प्रोग्राम्स देने की व्यवस्था गांवों के स्कूलों के लिए होनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय का पुनः ध्यान उस ओर दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि आज हमारी बृज की जनता, मथुरा की जनता मंत्री महोदय के मुंह से यह घोषणा सुनने की आशा कर रही है कि मथुरा में रेडियो स्टेशन कायम किया जायगा।

**Shri H. N. Mukerjee** (Calcutta Central): Mr. Chairman, Sir, I hear I have only an inauspicious total of 13 minutes to advance all my arguments, but I hope that you will let me have some extra time.

**Mr. Chairman:** He will have it (*Interruption*).

**Shri H. N. Mukerjee:** My friend Shri Raj Bahadur's predecessor in office is the Prime Minister of the country and her former deputy, a good friend of ours, is now a Minister of State, which makes me think how it is that our Information and Broadcasting Minister is not a member of the Cabinet. I say this is not a question of personality but because of the Ministry's importance in the scheme of things, and I do think that it is rather a bad thing that the Information and Broadcasting Ministry appears to have been downgraded to acertain extent.

In regard to broadcasting, which is the biggest aspect perhaps of the work of the minister over there, we do have an accumulated lot of grouses. Recently the Chanda Committee has expressed what it call its total disappointment at the unimaginative planning which is a feature of our broadcasting, because the programmes, generally speaking, are dull and dry. We have noted also from time to time very serious complaints against All India Radio. For instance, the complaint regarding the non-utilisation for nearly two years of a 100 KW transmitter with costly imported equipment, ageing in godowns and the site-selection roaming from Chandigarh to Dibrugarh is typical of the

leisurely ways of the All India Radio, which I do hope Mr. Raj Bahadur will see to it no longer continues.

I know sometimes All India Radio has done good work, specially during the difficult times that the country went through last year, but there is a long backlog of official apathy and misdirection, which has got to be rectified.

All India Radio, I am sorry to have to say, has a pitiful record over external broadcasts, reference to which has already been made in this House. AIR has about 160 hours a week for external broadcasts, whereas China with which country we seem to be developing a fixation, has 937 hours a week, second only to the quantum of USSR, and even such small countries as Cuba and North Korea have more than 200 hours a week. Besides, even apart from external broadcasts, does AIR want to make itself heard both literally and metaphorically? Their equipment is very worn out and we cannot even hear Calcutta properly. We hear about national integration and all that kind of thing. Let alone external broadcasts, we cannot even hear our own internal broadcasts. We are told about transmitters coming from foreign countries, which is a good thing as far as it goes, but it does not satisfy us, because the way things are being done is by no means indicative of progress in the future.

The Soviet transmitter, it seems, will not be installed till late in 1967 and will perhaps go on the air only in 1968. This delay has been due to the government's own inability to decide early what kind of transmitter we wanted from the USSR. This is one aspect of the way in which our AIR has been working.

As far as its news reporting is concerned, I have been constrained to notice that it dutifully headlines and displays neo-imperialist propaganda, even in contrast to our newspapers, who do not behave too well—AIR quoting Teheran and Paris for rumours of Soekarno's overthrow, days before anything of the sort happened. Even now that kind of thing has not happened. The overthrow of Soekarno, a greater leader of Asia, has not really taken place. But the way in which AIR puts across these things —it gloats over Soekarno having a fall and Nkrumah in Ghana going the way of all flesh and that kind of thing —these are howlers for which the countrys foreign policy will have to pay. All India Radio's job is to see to it that no hinderances are placed in the implementation of our friendly and independent foreign policy.

In regard to its own domestic affairs, AIR has staff artistes—some 2000 really capable and talented people spread all over India. But, unlike in other broadcasting organisations in other countries, their services are not permanent. The Chief Producer has a twelve-year contract, which is a good thing. But as far as the staff artistes are concerned, they can be transferred anywhere in India, but they have only a very short-term contract. They have insecurity of service and no pensions. No wage broad is appointed when they ask for it. Their pay is inadequate and that is their grouse. Their association is not recognised. The demands of this large body of really capable people who are running the AIR from day to day, who are the people who project their voices before the people, are left unrecognised.

Apart from staff artistes, inside their own organisation, AIR has specialised in a kind of treatment of artistes of reputation of which, I think it ought to be ashamed. Recently Chatur Lal, a top tabla artiste died. But it was discovered after his death and after wonderful obituary notices appeared in the newspapers that AIR had most ridiculously graded him as a B Class artiste and therefore there was not even a single recording of his tabla play. Being a very humble

[Shri H. N. Mukerjee]

B Class artiste, he was not considered worthy of that distinction! This kind of thing takes place in regard to people who are a by-word in the country and whom people know as really representative of our culture.

We talk about Sangeeta Sammelanis and that kind of thing. They are good as far as they go; but they do not go far enough; because the AIR does not seem to be making a search for talent. After all, it is not enough only to feature established celebrities who do not require encouragement from AIR. AIR has to go and find out talent in the country, develop them and bring them out, so that really and truly our musical and artistic life can be enriched.

Inside the establishment, there is so much discrimination, I could not understand, for instance, why at the time of the Tokyo Olympics, someone was sent to Tokyo to do the commentary who had never done a sports commentary in this country. If we wanted a sports commentator to go to Tokyo, someone should have gone who had already done sports commentary in our country. A Hindi commentator was sent, but he was put to the ignominy—Mr. Raj Bahadur should take note of it—of making comments only during the interval when the hockey match between India and Pakistan was played in Tokyo. A Burra Sahib was there, representing a paper in India, and because he had a British voice he was chosen to make the commentary, while the Hindi commentor was asked to comment only during the interval. This kind of thing is a little too much.

There are other failures also of AIR. When Lal Bahadur Shastri died, no feature programme was ready. Everybody has referred to it, including my friend, Mr. Hem Barua. The BBC in its World Service gave a touching and effective feature, but we could not do it.

I do not want to pick out only the deficiencies, but since there is very little time, I have to rush through them. We discovered during the last emeregncy period some features being put up which were not by any means good enough; on the country, they created a contrary impression. There was feature called "the Vacant Chair" produced by one of AIR's top men. It was an interview with a father whose son was killed in battle. It was psychologically entirely inept and many Members of Parliament have been constrained to remark about it. A person with an excellent radio voice, who might be top-class news reader is not necessarily a good feature writer at the same time. But it seems to be the policy of AIR to help only those who are already at the top and not to help those who are there who can be encouraged to develop their talents a great deal.

Reference has already been made in this House to certain most irresponsible acts committed by AIR—features like the story which was not true regarding the suicide dive on enemy installations during the Indo-Pakistan confrontation, which was a serious lapse. I do not think the distance between Akash Vani Bhavan and Vayu Bhavan is quite so much that they could not get in touch with the Air Force authorities, because they were embrrassed. When this kind of story, which was not true, was featured by AIR people came to believe it and then they were told it was not true. It was a most embarrassing situation and whoever was responsible has got to be ferreted out for particular punishment, because this kind of thing tarnishes the image of our country, which is already badly tarnished in the eyes of many parts of the world.

As far as our technical people are concerned, the engineers in AIR are frustrated. They point out how we procure materials which are easily available in the country like simple amplifiers, simple measuring instru-

ments, etc. from abroad. Recently under Japanese credit, an indent has been placed for a border station for materials which are made in India. We talk about import substitution and all that kind of thing, but in the meantime, this is what happens. We treat our own engineers like dirt. When the TV installation was made at Delhi by the West Germans, many unpleasnt situations were created because of their superior attitude towards our own engineers, who have done the same kind of thing before. Now the Russians are going to instal a megawatt transmitter in Calcutta. But there again, our engineers can do a job of work just as well and there is no reason why whether they are Russians or Japanese or Germans, our engineers should be kept out of the picture. The Minister, I hope, would tell us that he has completest confidence in our Indian engineers and he does not want to humiliate them. They have got a feeling that they are being humiliated. I hope, also, he would see to it that there is a central workshop in AIR where equipments could be repaired by special staff. AIR seems to be the only government department which does not have a central workshop of this sort, which we do need and which we can work.

Shri Hem Barua referred last time to the film *Neel Akasher Niche* done by a very distinguished director, Mrinal Sen, on which a ban was put. Shri Raj Bahadur was good enough to tell us that the ban has been lifted. But whoever was responsible for this kind of stupid action has to be told where he stands because this was a film which was applauded by the late Prime Minister, Jawaharlal Nehru and Dr. Rajendra Prasad when they saw it, and everybody welcomed it as a really good contribution.

In regard to television, on which I must say a word, I do not quite understand why Government does not explain to the country its sense of priorities. It is no good saying that television would help our education. I do not know—AIR is assisting educational processes in Delhi or somewhere —God knows what kind of educational assistance we get from AIR, but I remember a paper remarking on this business, of it being more economical according to the Chanda Committee's report to invest in television than to build schools. The newspaper editorially commented that "when Shri Subramaniam sees that food grows more easily on the TV screen than on India's soil he may, who konws, be inclined to follow the Committee's fabulous formula." Personally I do not like too much of this devotion to gadgetry. I have seen television; I am not too impressed. But do we at this point of time need to bother very urgently and expensively about television, because educationists in Calcutta say that Government is spending hundred crores on television but they cannot spare a few crores for them?

I come to my last point, Sir, because I have to rush over everything and delete a good deal of things I wanted to say, and that is in relation to the question of relating our socio-economic objectives to the newspaper industry. But the Information and Broadcasting Ministry has never tackled it. It has failed to check monopoly in newspaper industry. The Government is not unduly anxious to formulate any long-term plan for a balanced growth of the Press and anti-monopoly activities. During Question Hour it came out that there was a flourishing blckmarket in newsprint and in Calcutta a newspaper collected its newsprint but the paper never came out. The Diwakar Committee has made recommendtions, for instance, about the price-page schedule and a ceiling on advertisement space. The Diwakar Committee has recommended that even if the Constitution needs amendment let this be done at once. It has also pointed out that on account of the emergency being still there we do not even need a constitutional amedment to have price-page schedule. But the Minister, early this morning, said that the

[Shri H. N. Mukerjee]

rise in newspaper prices is a good thing. I do not know. The price-page schedule has not come. Without a price-page schedule being put into operation here are the newspaper magnates who are asking more money from the people. Here is the newspaper published by the Indian Federation of Working Journalists which gives facts nd figures about how the newspaper price rise is absolutely unjustified.

In regard to publication there are many gaps. Gandhiji's collected works are brought out in English and also in Hindi. Why not in the other languages? The Ministry is bringing out Pandit Jawaharlal Nehru's collected works or something of that sort. We were told that royalties would be payable to whoever is the heiress. This is a rather embarrassing thing. After all, Jawaharlal Nehru's ideas can be spread by other means than by the Minister of Information and Broadcasting publishing his collected works straightaway. When the beneficiary is going to be the Prime Minister of this country in regard to royalties from that, Government at least should hold its hand. That kind of thing is not done anywhere, it should not be done.

Because the Deputy Leader of the Swantantra Party had devoted his entire speech to the question of an independent television authority entirelly independent of Government, I want to say this. I know that sooner or later television is going to come to this country. There is no doubt about it. But let not Government be inveigled by the kind of interest which Shri Masani represents. The very fact that he devoted his entire speech to championing the cause of people who might be running the television authority shows how certain lobbies are at work in this country against which the Ministry of Information and Broadcasting has got to take steps. An independent authority, like independents in public life, is very often undependable. We cannot depend upon them. Let the Government take it over, whenever television comes. This kind of gadgetry we may not be able to afford very soon and in ample measure, but whenever it comes Government must be there because Government is answerable to the people and Government must be their to run it, and no attention should be paid to such interests who so obviously argue the case on behalf of some people who are the "big money bags" in our country.

I say, therefore, there are many matters in regard to which the Minister of Information and Broadcasting has got to put his own house in order. But I do hope that, forgetful of the fact that Government has for some mysterious reason denigrated his Ministry by not putting him in the Cabinet, let him go ahead and work in a manner so that we can talk about him much more generously than we do now, because he is a friend of ours, we have known for so long and I personally would have been very much more happy if I could compliment him a great deal more than I have done.

**Shrimati Maimoona Sultan** (Bhopal): Mr. Chairman, Sir, while speaking on these Demands I shall mainly confine myself to the working of the All India Radio, for there is very little time at my disposal. Before I do so, I wish to say a few words about television in our country.

Sir, the plans to have television in the country has been acclaimed by many people; it has also been criticised by quite a few. Personally, I believe that it is a very revolutionary step which, if implemented with maturity and imagination, would go a long way in shaping the destiny of our people in many fields such a agriculture, eduaction and so on. Therefore, I welcome it. I am also of the opinion that television is not an item

of luxury as was pointed out by Shri Masani, but it is a necessity for a developing country such as ours, and if we accept the fact, as we should, that television promotes enormously the cause of education the cause of agriculture and so on, then ways and means could always be found out by the Government to meet the situation and to meet the challenge. There is one suggestion made by the Chanda Committee, that television should be handed over to a corporation. I support this suggestion. But I am of the opinion that in the initial stages of development, when television is going to have all sorts of teething trouble, Government should have full authority and control over this organisation. Later on, when the pace of work and a pattern has been set, it can be handed over to a corporation which could utilise it for the benefit of the people.

Now, before I proceed any further I wish to draw the attention of the Minister to the violation of article 4 of the Tashkent Declaration by Pakistan. Sir, the world knows we are implementing the terms of the agreement in letter and spirit; but it is not so in Pakistan. The Tashkent Declaration, for various reason, is a sacred document for us. Only the other day at one Urdu Mushaira an Urdu poet hailed the spirit of the Tashkent Declaration in these words:

तुम एक बार आओ तो हम मिल के दोस्तों
मीसाके ताशकंद की तसवीरें जां बनायें ।

"If only you could embrace our friendship, then we can make the spirit of Tashkent part of our lives". This is the spirit in which our people look upon this agreement. But what we gather from the Pakistan press, what we know from newspapers such as *Navai Waqt, Jang, Dawn* and many others, and what the speeches of Pakistani leaders like President Ayub Khan and Mr. Bhutto tell us, makes it clear that they are not restraining themselves from damaging the spirit of Tashkent. I, therefore, urge upon the Minister to check upon these details and then re-shape the policy accordingly in regard to the publicity media under its control. That is absolutely necessary; it is very important; because we do not want to be caught napping again this time. In any case, we owe it to the people that they should be told facts bluntly as they exist.

Now I shall come to broadcasting. I am sorry to say that broadcasting has received rather shabby treatment from the Government. The Planning Commission has allotted to it a very niggardly sum, which is hardly in tune with the times. It is no exaggeration to say that if Government could take this broadcasting medium a little more seriously than what it does at the moment there could be a revolutionary change in the pattern of thinking of the farmers, carrying the youth and the children. I think the Planning Commisison has to be awakened to this reality and the sooner we do it the better for us.

Since All India Radio is a part of the Ministry of Information and Broadcasting, I will now say a few words about the Ministry. I am sorry to say Government has not accorded this Ministry finally the recognition that it deserves. At one time it was headed by a man of such eminence as Sardar Valabhbhai Patel, who was also the Deputy Prime Minister; then after some time Mrs. Gandhi took over and now Shri Raj Bahadur is in charge of this portfolio. We all know is a very competent Minister with an excellent record of work in the past years. But, again there has been a change in the status of the Ministry. I see no reason really as to why this Ministry should not be ranked, as Professor Mukerjee has said, with, say, the Ministry of Commerce, the Ministry of Education or the Ministry of Steel and Mines. I am sure that the hon. Minister will convey to the Prime Minister, the views of the Members on this matter.

Now I shall come to certain aspects of the All India Radio. I would say

[Shrimati Maimoona Sultan]

that it is an organisation seething with discontent and frustration in many respects. The All India Radio is tied up with its past; thanks to the authorities who at different times at different levels have either in their ignorance or in arrogance, have done more damage to this institution than good. Somehow, the All India Radio always reminds me of the picture of a toiling man who looks hopefully towards the future but whose steps are uncertain because of the cartload of unhappy yesterdays he carries on his head. We shall be very grateful to the Minister if he could release this organisation from the fetters of the past and put the house in order for unless and until it is done we should not except any second results from broadcasting.

Speaking about the chaotic conditions in the All India Radio, I wish to draw the attention of the Minister to the condition of the programme executives. These are the people who bear the brunt of most of the planning and execution of programmes. What is their fate? I know for certain that there are more than 150 programme executives at the moment who have not known a single promotion in all their lives even though they have put in 15, 18 or even 20 years of service. The trouble is that All India Radio, although it is an all-India service, is not included in the All India Services such as Administrative Service, Foreign Service or, Railway Service. Therefore, I would urge upon the Minister that in the interest of efficiency of working the pay scales of the officers have to be revised and they should be given opportunities for promotion within a reasonable time.

I shall now turn my attention to the performance of the All India Radio during the recent past. We remember that at the time of the Chinese aggression the All India Radio was simply stunned into inaction. But this time it was not so. This time it rose to the occasion and kept up the morale of the people. It has been an unforgettable experience to listen to the majesty of words of Melville de Mellow and also the features that he has produced; they made the nation throb with emotions. There have been many other features such as Focus and Topic For Today which were completely revitalised. The credit for all this should go to the Director-General and the personnel of the All India Radio who must have worked tirelessly to make them a success.

While our home-broadcasts have been of excellent quality, unfortunately, I cannot say the same thing about our external broadcasts. They are dismal failures very unimaginative and very uninspiring. In our external broadcasts we are yet to grasp the fact that the number of target areas our external agencies have, are vastly different from one another constitutionally, politically and racially; and we have to cater to them according to their needs. For instance, it is no good telling the Arab countries that Pakistan is a theocratic State. That is not going to cut ice with them for the simple reason that those countries themselves are based on religion and monarchy. Therefore, if we have to win over those countries more and more to our side we have to do it in a more imaginative and more subtle manner.

Certain items from home broadcasts are repeated in our external services without proper selection, editing or adaptation. For instance, during the time of the crisis our leaders were making appeals for communal harmony. While it may have great significance for us, it is not so for the people abroad. On the other hand, it may give the impression as if our people are splitting apart.

Finally, I would request the Ministe to give a little more attention to places like Bhopal. I have been urging the Minister for quite some time

that Urdu programme for half an hour should be started from Bhopal, the reason among others is that Urdu is still very close to the people of Bhopal. It is the language of the people and it is but fair they should be approached in the language they understand and appreciate. Besides this, it will also help the local talent to come up. I am sure the Minister will give it due attention.

**Shri Ansar Harvani** (Bisauli): Mr. Chairman, Sir, I have always considered the Ministry of Information and Broadcasting as one of the most important Ministries of our Government because it is the function of the Ministry to convey the warmth and glow of freedom to the Indian people and to convey the hopes and aspirations of the Indian people to the Government. There were days when this Ministry was presided over by a man like Sardar Vallabhbhai Patel. Then two successive Ministers came who were given the status of Minister of State. Year after year I pleaded on the floor of this House that this Ministry should be raised to the status of a Ministry under Cabinet Minister. I was glad that the late Pandit Jawaharlal Nehru acceded to this request and Dr. B. Gopala Reddi was appointed as Minister with Cabinet rank in charge of this Ministry. As has been pointed out by Shri Hiren Mukerjee and Shrimati Maimoona Sultan the present Minister is a very experienced and able Minister. I hope and trust that our request will be conveyed to the Prime Minister that he should be given the status and rank of a full-fledged Cabinet Minister.

I have to offer brickbats as well as bouquets to the present Minister. I must start with brickbats. A decade ago the Press Commission had recommended that the monopoly of the press should be broken, but nothing has been done so far. Parliamentary democracy in this country is at ransom in the hands of three press barons. Most of the revenue of advertising which is being given by the Government is given to these papers which are preaching communal hatred, which are preaching everything against socialism and everything against this Government. I do not want that the press in this country should be muzzled. I do not believe that the freedom of the press should be curtailed. But, at the same time, I believe that the freedom should not be given to the press in this country in a way which will undermine the policies and programmes of socialism. I know it very well that these press lords, press barons want to create in this country a society in which the underdogs may not grow. Therefore, these tendencies should be curbed.

**14.00 hrs.**

I hope and trust that the hon. Minister will seriously see to the recent report which has been given by Shri Diwakar about the small-scale newspapers and a beginning will be made so that at least 50 per cent of the revenue of Government advertisements, 50 per cent of the revenue of railway advertisements and 50 per cent revenue of the State Corporations' advertisements should go to the smaller papers. I hope and trust that soon he will create a finance corporation which will be able to finance these papers in the matter of having presses and of purchasing newsprint and other things. It is necessary that the power of the press barons should be curtailed. If parliamentary democracy is to survive in this country, we have to see that the smaller papers should grow and the monopoly of the press is broken, otherwise, I see a very bleak future for democracy in this country.

All India Radio has been one of the most criticized institutions of the Government of India, but I can say with full authority at my command that in recent years All India Radio has made certain progress. In recent years things in All India Radio have considerably improved; but still now they need improvement. The Hindi language which is being used by the All India Radio is absolutely unintelligible to those people who have claim

[Shri Ansar Harvani]

to speak Hindi either in Delhi or in Lucknow or in Bhopal or in Rajasthan. Therefore, it is necessary that the Hindi language being used by All India Radio should be simplified and made intelligible to the people.

Urdu, which is a great language of this country and which is spoken in many parts of the country, is completely being neglected by All India Radio. Some years back the Urdu Majlis programme had been started by All India Radio and I will request the hon. Minister to examine the popularity of that programme. He will find that there is hardly any programme which is so popular as the programme of Urdu Majlis in Urdu-speaking and Hindi-speaking regions. But, unfortunately, Urdu Majlis is given only half an hour. I will request the hon. Minister to increase the time for this broadcast and to have Urdu broadcasts more frequently, to give more time on the air to Urdu broadcasts. Hyderabad, Lucknow, Delhi—these are all Urdu-speaking stations and I see no justification why Urdu should not be used in these regions and given a better place.

I would also pay my tributes to the Vividh Bharati programme. There were the days of puritan music of Dr. Keskar. I am glad that those days are over. They were the days when people used to listen only to Radio Ceylon; but, now with Vividh Bharati coming up, people listen to All India Radio also. I hope and trust that this programme will be extended to other stations also so that popular music may be heard by the people who want to hear popular music.

The News Department of All India Radio is very much criticized. It is true that there is a lot of scope for improvement in the News Department but I can say that their feature, Newsreel, is of an excellent quality. It is a very nice programme. The newsreel, which depicts interviews between the All India Radio and the various celebrities who come to this country, is being listened not only in this country but outside this country also. I hope and trust that this feature will be improved and more popularised and more extended.

One word about external publicity. It is very unfortunate that in the Government of India everything is duplicated. We have got an information department in the Information and Broadcasting Ministry but external publicity has been handed over to the External Affairs Ministry. I hope and trust that the present Minister will insist upon the Prime Minister that external publicity should be handled by the Ministry of Information and Broadcasting and not by the External Affairs Ministry because we have got the resources, we have got the Press Information Bureau, we have got the Publications Division, we have got the All India Radio, we have got the audio-visual publicity organisation and with all these organisations we can handle that publicity in a much better way than the External Affairs Ministry is doing. It will mean economy, non-duplication and improvement. Therefore, the hon. Minister should assert himself and see that external publicity is brought under the purview of the Ministry of Information and Broadcasting.

**Shri Muthyal Rao** (Mahbubnagar): Very good suggestion.

**Shri Ansar Harvani:** Then there is the Publications Division. The Publications Division also is an empire in various departments. I understand that there is a Publications Division in the Ministry of Information and Broadcasting; there is a Publications Division in the Ministry of Education; there is a Publications Division in the Ministry of Finance and there is a Publications Division i nthe Ministry of Commerce. This is all duplication; this is all sheer waste. I hope and

trust that all these publications organisations of the various ministries would be brought under the control of the Ministry of Information and Broadcasting and the extra expenses which are being incurred by the various ministries who are fond of having their own empire would be curtailed.

**Shri Tyagi** (Dehra Dun): We agree.

**Shri Ansar Harvani:** With these words, I hope and trust that the hon. Minister, who is new to this ministry . . . (*Interruption*).

**An hon. Member:** He is an old Minister.

**Shri Ansar Harvani:** I have seen him piloting the ship in the Ministry of Transport and I hope he will pilot the ship of this ministry successfully and to the real goal.

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** (बिजनौर) : सभापति जी, मैं अपने मित्रों से सहमत हूं कि सूचना और प्रसार मंत्रालय का महत्व इसी से प्रकट है कि देश के स्वतन्त्र होने के बाद इस विभाग का दायित्व स्वयम् तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने लिया और उन के बाद श्री दिवाकर जैसे गम्भीर और अनुभवी व्यक्ति इस विभाग के मिनिस्टर रहे । मुझे खेद है कि पिछले कुछ वर्षों में आकाशवाणी को और इस विभाग को जो महत्व दिया जाना चाहिये था उस प्रकार महत्वपूर्ण इस विभाग को नहीं माना गया । लेकिन नहीं कह सकता कि जाने या अनजाने में, अब यह विभाग श्री राज बहादुर जी को दिया गया है । श्री राज बहादुर से यह संसद् और यह देश अच्छी तरह परिचित है । वे परिश्रमी और मेहनती व्यक्ति हैं । अपने विभाग के हर कार्य में तह तक जाना चाहते हैं और वहां के प्रत्येक कार्य का नई दिशा देने का प्रयास करते हैं । मुझे विश्वास है कि सूचना तथा प्रसार मंत्रालय में उनका आगमन देश को एक नई दिशा देगा और इस मंत्रालय के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा । मैं उन के मंत्री होने पर अपनी ओर से उन का अभिनन्दन करता हूं ।

आकाशवाणी प्रचार का सब से बड़ा और सब से समर्थ माध्यम है, लेकिन दो कारणों से उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है । एक कारण है हमारे देश में शक्तिशाली ट्रांस्मिटरों का अभाव और दूसरा कारण है आकाशवाणी द्वारा भारतीय भाषाओं को अपेक्षित मात्रा में प्रोत्साहन न दिया जाना । जहां तक ट्रांस्मिटरों की बात है, मुझे इस बात को कहते हुए कष्ट है कि अभी तक ट्रांस्मिटर की समस्या राजनीतिक कारणों से बराबर उलझती ही चली जा रही है । चीनी आक्रमण के समय यह प्रश्न उठा था तब देश में बड़ी दृढ़ता से अनुभव किया गया था कि शक्तिशाली ट्रांस्मिटर जल्दी से जल्दी यहां पर आना चाहिये । लेकिन उस के बाद राजनीतिक दावपेंचों में पड़ कर कि किस देश से उसे खरीदा जाये, कैसे खरीदा जाये, उस के लिये रुपी पेमेन्ट हो या विदेशी मुद्रा में मूल्य दिया जाये, इन सब चक्करों में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि टेलिविजन की भी देश में बहुत उपयोगिता है लेकिन टेलिविजन आरम्भ करने का उतना तात्कालिक प्रश्न हमारे देश के लिये नहीं था जितना कि शक्तिशाली ट्रांस्मिटर का लाना था । अगर सरकार अब तक इस विषय में ढील करती रही तो अब कम से कम वह इस भूल को तेजी से सुधारे ।

जहां तक दूसरी बात है अर्थात् आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भारतीय भाषाओं की उपेक्षा मैं एक ही उदाहरण उसके लिए देना चाहूंगा । और मेरा अनुमान है कि श्री राज बहादुर जी के कानों तक वह गया भी होगा पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों सन् 1947 के पहले एक देश थे । दोनों में समान रूप से

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

अंग्रेजी का प्रचार था । अब भी भारतवर्ष में विशेष रूप से अंग्रेजी का कोई प्रचार नहीं हुआ है, यद्यपि यह जरूर है सरकार अंग्रेजी के मोह में अभी तक फंसी हुई है । किन्तु पाकिस्तान ने अपनी भाषा के सम्बन्ध में क्या कुछ किया है उस का तुलनात्मक विवरण देते हुए दो शब्द कहूंगा। पाकिस्तान रेडियो ने 15 नवम्बर, 1965 को प्रातः पौने आठ बजे जो अंग्रेजी बुलेटिन प्रसारित हुआ उस की एक सूचना का हिन्दी अनुवाद ज्यों का त्यों पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ।

"कल रेडियो प्रसारण के सम्बन्ध में जो नई नीति घोषित की गई थी, उस के अनुसार रेडियो पाकिस्तान आज से 1.10 दोपहर, 5.10 शाम और 10.00 बजे रात को प्रसारित होने वाले तीन अंग्रेजी बुलेटिन बन्द कर रहा है । इस के अतिरिक्त रात को 8.20 पर अंग्रेजी में प्रसारित की जाने वाली समाचार समीक्षा और रेडियो पाकिस्तान के सभी केन्द्रों से रिले होने वाले स्थानीय अंग्रेजी बुलेटिन भी आज से बन्द किये जा रहे हैं । अंग्रेजी में केवल दो बुलेटिन होंगे । एक सुबह एक शाम को । सवेरे का अंग्रेजी का बुलेटिन 15 मिनट के बजाय 10 मिनट का होगा ।"

पहले पांच बुलेटिन अंग्रेजी के और एक अंग्रेजी समीक्षा पाकिस्तान रेडियो से होती थी पर अब केवल दो बुलेटिन पाकिस्तान रेडियो से प्रसारित होते है । इस के मुकाबले में भारतीय रेडियो की क्या स्थिति है ? जिस समय पाकिस्तान का आक्रमण हुआ उस समय उन्होंने अंग्रेजी के 9 बुलेटिन रखे और हिन्दी के 8 बुलेटिन रखे । कुछ फीचर भी आकाशवाणी से प्रसारित किये गये । अंग्रेजों के प्रति दिन लगभग 6 फीचर प्रसारित किये जाते थे और आकाशवाणी के सभी केन्द्र उन को रिले करते थे, और वह सुनने का अच्छा समय होता था अर्थात् 8 30 बजे उस समय उन को सुनाया जाता था । उस के मुकाबले में हिन्दी के कुछ फीचरों के सम्बन्ध में जब समाचारपत्रों में आलोचनायें प्रकाशित हुई कि हिन्दी की या दूसरी देशी भाषाओं की इस प्रकार की उपेक्षा क्यों है तब कुछ फीचर रिले किये गये ।

**14·08 hrs.**

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

लेकिन एक तो वह सब केन्द्रों से रिले नहीं किये गये, दूसरे रिले करने का जो समय था वह रात को दस बजे या दस बजे के बाद जब आम तौर से सब लोग सो जाते हैं उस समय यह फीचर वहां से प्रसारित किये जाते थे । अंग्रेजी का इतना बोलबाला पाकिस्तानी आक्रमण के समय था कि उस समय जो देशी भाषाओं के या देशी लोकगीत आकाशवाणी से प्रसारित होते थे जैसे डोला है, आल्हा है मराठी का पवाडा है या तेलगु का बुरकिया है । इन गीतों के प्रारम्भ में जो घोषणा होती थी वह घोषणा भी अंग्रेजी में की जाती थी । अब डोला या आल्हा सुनने वाला जो कोई व्यक्ति होगा क्या वह हिन्दी न जानता होगा ? लेकिन आकाशवाणी से जो इनको प्रसारित करने वाला व्यक्ति था वह यह कहकर के आल्हा सुनवाता था :

Now you hear the Bundel Khand song Alha.

यानी आल्हा सुनने वाले को भी अंग्रेजी में पहले उसका परिचय देने की जरूरत है । यह आकाशवाणी के अंग्रेजी मोह का एक उदाहरण है ।

अंग्रेजी पत्रों में अपनी वाहवाही लूटने के लिए आकाशवाणी का विभाग क्या करता है उसका मैं एक परिचय आप को देना चाहता हूं । क्योंकि दुःख से हमारे मिनिस्टर भारत की आत्मा को अंग्रेजी पत्रों के माध्यम से पढ़ते हैं और उनके बड़े बड़े सेक्रेटरीज जितने हैं वह भी अंग्रेजी पत्रों के माध्यम से देश की जानकारी लेते है । उसका परिणाम यह है कि

विभाग के अधिकारी अंग्रेजी पत्रों के सम्पादकों को और उनमें काम करने वाले व्यक्तियों को बड़ी बड़ी कीमतें प्रति दिन देकर बुलाते हैं। उदाहरण के लिए आकाशवाणी में फोकस, टापिक फार टुडे और फीचर, यूनिट टाकसेल आदि हैं। इन्हें तैयार करने के लिए नियमित कर्मचारी यहां नियुक्त हैं जिनको हजार से लेकर डेढ़ हजार तक की मासिक तनख्वाह दी जाती है। फिर क्या आवश्यकता थी कि कुछ ऐसे व्यक्ति वहां पर बुलाये जाते थे जिनको 60 से लेकर 100 रुपये तक प्रति दिन दिये जाते थे और उनसे फिर यह टापिक और फीचर्स लिखवाये जाते थे ? केवल इसलिए कि इस पैसे को देकर उनके माध्यम से अंग्रेजी पत्रों में अपनी प्रशंसा छपवायें जो मिनिस्टरों के कानों तक पहुंचे और जिससे वह इनके सम्बन्ध में अपना अच्छा मत बनायें।

जहां तक विदेश विभाग का सम्बन्ध है विदेश सेवा की स्थिति क्या है ? उसका भी मैं उदाहरण उपाध्यक्ष जी, देता हूं। तीन वर्ष पहले फिजी के सम्बन्ध में 12 से लेकर डेढ़ बजे तक डेढ़ घंटे हिन्दी का कार्यक्रम प्रसारित होता था। फिजी की अधिकांश जनता हिन्दी भाषाभाषी है। लेकिन जनवरी 1965 से जब से संविधान की दृष्टि से हिन्दी देश की प्रमुख भाषा हुई, आकाशवाणी ने फिजी के कार्यक्रम बन्द कर दिये गये। यह हिन्दी को मान्यता आकाशवाणी से मिली। इसी तरह से फिजी, मारीशस और ब्रिटिश गायना जहां पर भारतीय अधिक संख्या में रहते हैं, चाहिए तो यह था कि उनके कार्यक्रमों को बढ़ाया जाता, लेकिन यहां नीति क्या है कि जो तीन चार साल पहले विदेशों के लिए चार बुलेटिन प्रसारित होते थे उनमें से एक बन्द कर दिया जाता अब मैंने सुना है कि पहली अप्रैल से एक ऐसा आदेश होने जा रहा है कि 9.50 का जो हिन्दी बुलेटिन विदेशों के लिए जाता है उसको भी बन्द कर दिया जाय और शेष जो दो बुलेटिन हैं उनका भी दस दस मिनट का समय घटाकर के पांच पांच मिनट कर दिया जाय। यानी विदेशों के लिए जो 40 मिनट समय हिन्दी को दिया जाता था आकाशवाणी से अब वह केवल दस मिनट होने जा रहा है।

जहां तक बुलेटिनों की आत्मा का सम्बन्ध है इसी से अनुमान लगाइए कि जिस समय पाकिस्तान का आक्रमण चल रहा था अंग्रेजी के भक्त किस प्रकार से राष्ट्रीय समाचारों की उपेक्षा करते रहे और अराष्ट्रीय समाचारों को प्रभुत्व देते रहे बलवन्तराय मेहता का जिस दिन देहावसान हुआ, प्रातःकाल जो सबसे पहला हिन्दी बुलेटिन था उसने यहीं से आरम्भ किया कि हम बड़े दुख के साथ देश को यह सूचना देते हैं कि गुजरात के मुख्य मंत्री श्री बलवन्त राय मेहता का विमान दुर्घटना में देहावसान हो गया। लेकिन अंग्रेजी का बुलेटिन इसको इतना महत्व नहीं देता। वह पहले और समाचार सुनवाने के बाद अन्त में कहता है कि श्री बलवन्त राय मेहता का भी देहावसान हो गया। इसी प्रकार से जिस दिन चीन ने तीन दिन का अल्टीमेटम हिन्दुस्तान को दिया था उसी दिन भारत के रक्षा मंत्री ने एक सन्देश देश के नाम प्रसारित किया। लेकिन रक्षा मंत्री का सन्देश बाद में प्रसारित किया गया और जो चीन की धमकी थी वह पहले प्रसारित की गई। तो जब बुलेटिनों की नीति यह है, वहां कार्य करने वालों की नीति यह है तो क्या होगा ? अभी पीछे प्रधान मंत्री के चुनाव में जो हुआ, मैं उस दुखद अध्याय को छेड़ना नहीं चाहता। आकाशवाणी समाचार प्रसारित करती थी या वातावरण निर्माण करने का काम करती थी ? बंगाल के अन्दर अभी जो उपद्रव हुए, लेफ्टिस्ट कम्यूनिस्टों के समाचारों को किस तरह से प्रोत्साहन दिया गया, क्या इन तमाम बातों को देश के निवासी नहीं समझते कि किस प्रकार समाचारों का संग्रह किया जाता है और उनको अपेक्षित मात्रा में महत्व देने के बजाय अनपेक्षित महत्व दिया जाता है ?

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

इसलिए मेरे कुछ सुझाव हैं जिनको मैं संक्षेप में कहता हूं एक तो हिन्दी के प्रमुख राजभाषा होने पर जो बुलेटिन हिन्दी के हैं वह हर कार्यक्रम में पहले प्रसारित किये जायें और देश के सब स्टेशनों से वह रिले किये जायं । आप पूछेंगे कि इससे क्षत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों में हानि पड़ जायगी । मेरा कहना यह है कि क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों में कोई कटौती न की जाय बल्कि अंग्रेजी के कार्यक्रमों में कटौती करके हिन्दी के बुलेटिन सब स्टेशनों से प्रसारित किये जायं । विदेश विभाग की तरह आकाशवाणी में एक राष्ट्रीय सेवा विभाग की स्थापना की जाय । हिन्दी समाचार और हिन्दी के जितने भी कार्यक्रम हैं इनके लिए एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना इसके अंदर होनी चाहिए । आपके पास लखनऊ, जयपुर, पटना, भोपाल, वाराणसी में प्रस इन्फार्मेशन ब्यूरो की ओर से हिन्दी की टेलीप्रिन्टर सर्विस बाकायदा लगी हुई है तो जो हिन्दी भाषी राज्य हैं उनकी विधान सभाओं के समाचार या उनके समाचार हिन्दी में लेकर प्रसारित करें इसके अन्दर आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

दो बातें मैं अन्त में फिल्म सेंसर बोर्ड और समाचार एजेंसियों के बारे में भी कहना चाहता हूं । फिल्म सेंसर बोर्ड की आज क्या स्थिति है ? हमारे देश में हल्के फुल्के दृश्य जिस तरह से आज तैयार हो रहे हैं, अर्द्ध-नग्न दृश्यों को जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है उनका आचार्य विनोबा भावे जैसे संत ने भी विरोध किया था । घिसे पिटे वही पुराने कथानक हैं, इस दिशा में भी आपको कुछ सोचना चाहिए । मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि फिल्मों के अन्दर जितना अच्छा सरसता का अंश है उसको सर्वथा समाप्त कर दिया जाय । श्री राज बहादुर जी तो ब्रज के निवासी हैं, राधा के प्रदेश के निवासी हैं, मैं नहीं समझता कि उनके रहते हुए सरसकता बिलकुल ही चली जायगी लेकिन इतना मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति के भी तो वह अमी हैं, इतना तो कम से कम वह नहीं करेंगे कि फिल्मों के नाम पर देश में बिलकुल विदेशी चित्रों का अन्धाधुन्ध अनुकरण किया जाय ।

जहां तक समाचार एजेंसियों का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में मेरा कहना है कि जिस तरह से पी०टी०आई० को आप महत्व देते हैं उसी तरह से दूसरी न्यूज एजेंसीज को भी जैसे यू०एन०आई० वगैरह हैं, उनको भी महत्व देकर बढ़ायें । इसके अतिरिक्त भारतीय भाषाओं की जो समाचार समितियां हैं या तो एक अच्छी पूर्ण सशक्त समितिस्थापित करें और यह अगर नहीं होता है तो जसे हिन्दुस्तान समाचार है जो राष्ट्रीय समाचार देशी भाषाओं के माध्यम से देता है उसको आप प्रोत्साहन दें जिससे यह और भी अधिक बढ़ सके ।

अन्त में एक यह बात कह कर के समाप्त करता हूं कि विज्ञापन देने के सम्बन्ध में सूचना और प्रसार मंत्रालय अपनी नीति में परिवर्तन अवश्य करे । जब भी इस मंत्रालय के अनुदानों की चर्चा आती है तो इस बात पर आलोचना होती है कि सरकार केवल उन पत्रों को विज्ञापन देकर उपकृत करती है कि जो सरकार की प्रशंसा करते हैं । सरकार के लिए तो देश के सारे पत्रों को एक समान रूप से लिया जाना चाहिए । दिल्ली राजधानी से दो दैनिक पत्र निकलते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हू कि देश में उनके पाठकों की संख्या बहुत बड़ी है पर उनको विज्ञापन नहीं दिये जाते हैं । तो इस दिशा में भी दोहरी नीति न अपनायी जाय । मुझे विश्वास है कि श्री राज बहादुर जैसे गम्भीर आदमी के हाथ में यह विभाग आया है तो कुछ निर्णय भी गम्भीरता के साथ में अब लिये जायेंगे ।

**Shri Kasinatha Dorai** (Aruppukkottai): Mr. Deputy-Speaker, Sir.....

**श्री हुकम चन्द कछवाय** (देवास) : आप व्यवस्था दें अध्यक्ष महोदय, सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

**Mr. Deputy-Speaker:** The bell is being rung.

**Shri Kasinatha Dorai:** Sir, I rise to support the demands of the Ministry of Information and Broadcasting. I would like to congratulate the Ministry for the excellent work done by them, specially by the radio station in Jammu and Kashmir.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** No quorum.

**Mr. Deputy-Speaker:** The hon. Member may wait. The bell is being rung. . . . now there is quorum. He may continue now.

**Shri Kasinatha Dorai:** Not only colleagues from Jammu & Kashmir have attested to this but also the members of the Defence Services from the south have spoken very highly of the excellent work done in that area.

Frequent references have been made by members to the promotion of this Ministry; hitherto they have been said in the way of best wishes, but today Prof. Hiren Mukerjee has produced a plausible argument for this purpose and I hope the Government's attention will be drawn to promote this Ministry to a higher level.

I would like to appreciate the work started as the Institute of mass communication by the Ministry. But at the same time, I would like to say that the public have not been properly informed of the very many good things that Government is doing. As a matter of fact, in my own Constituency, a number of block centres have not opened their information centres; that means, so much of literature printed by the Centre is lying waste without being of any use to the public. Even some of the gram sewaks may be given some kind of training; besides those people who are getting a special training under the scheme, they may also be given training to contact the masses and tell them of some of the Government's plans—Five-Year Plans and all that—so that we can get some kind of co-operation from the public when we go to execute these plans and policies.

Lot of literature is printed in English; it is not of much use in southern States, especially in Madras State. It will, therefore, be very useful if it can be translated into regional languages.

Coming to the tribal programme, I think it will be very useful if information about other tribes also is given in a special programme and is supplied to a particular tribe so that a kind of information can be given to them to promote national integration. For instance, we speak so much about Nagas; it will be very useful if some kind of research is done on the subject of Naga tribes; though we thank the Rev. Scott for having brought about educational, religious, medical and institutional changes into that area, somehow that missionary has created an impression in Nagaland that the Naga tribes are some people separated from the rest of India. In this connection, I would like to mention a book—it is available in Parliament Library written by a Ceylonese, Navaratna, entitled "Tamils in Ceylon" where very happy and useful references have been given about the Naga tribes both in north Ceylon and in Tamilnad and also in Kerala and from where we can learn of so much of civilisation about those people.

On the question of music I would like to say a few words. Though 50 per cent of the time has been allot-

[Shri Kasinatha Dorai]

ted to it, no special head for music is found in the report; there are, of course, sub-heads but music deserves a separate head under the scheme. Especially in a country like India where we can boast of a hoary past, much emphasis should be laid on the classicals of everything, whether it is music or literature or civilization; at least the masses should be able to appreciate it. Those were the days in the past when all the classics were the close preserve of a privileged few, but now the masses will have to appreciate all those; for instance, a knowledge of classical music will help integration. Just as we use the word 'Defence-oriented', we must use the word 'integration-oriented' and all our schemes should be on those lines. In this connection I would like to mention that, in Delhi, an academy, Shankara Academy, has been started—Shankara was a great national integrator. Government may usefully contact such private bodies and give more publicity to their activities. Similarly an institution has been started in the south called Ramalinga Mission, which gives the quintessence of the southern civilisation; that also may be given some publicity.

Then there is a reference to the language issue. There has been some reference to the rioting in Tamilnad last year. The Ministry can usefully inform the public and give clear information and also remedial measures in time so that recurrence of such riotings may be avoided.

With regard to communal harmony, simply saying that Hindus, Muslims, Christians and people of all religions must live together may not help. I say this because a number of interested parties are stressing on the points of disagreement to the public and are developing hatred among one another. I, therefore, feel that the points of agreement between the many cultures should be highlighted by the radio.

One thing that should be appreciated is the National Discipline Scheme. I do not know its broad features; I have not had the time to study it; anyway, this reserves a mention.

About external publicity, I would like to suggest that documentaries should be prepared with regard to the treatment of minorities, for instance, how the Muslims are treated in India, and these documentaries may be shown with advantage in foreign countries, especially in the middle east countries, to remove the prejudices likely to be created by interested countries.

Reference has also been made to Indo-U.A.R. culture. Here I would like to suggest that we may give some information to the neighbouring Muslim countries about some of our shrines like Ajmer and other shrines in the north and Nagoor and Ervadi in the south. At the same time we may also request the U.A.R. countries to give us a little information about their old culture like the culture centring around sphinx, pyramids, etc.

**Mr. Deputy-Speaker:** The hon. Member may try to conclude now.

**Shri Kasinatha Dorai:** I may be given a few more minutes. I rarely speak.

**Mr. Deputy-Speaker:** Ten minutes are given for each.

**Shri Kasinath Dorai:** Countries like India and U.A.R. have got certain points of agreement in that we both believe in non-alignment, secularism and all that. The visits of statesmen from many countries, from USSR, America and others, also emphasize that we treat all people alike.

Cultural delegation and social delegation also may be exchanged between U.A.R. and India.

About catering to the jawans, I would like to say that all the precious things of our motherland may be prepared and shown to them for keeping up the spirit besides the items of entertainment value.

With regard to the use of party flags, some members also have told me that they are exhibited. Here, let us state clearly all the difficulties that are likely to crop up later on. Unless these things are censored in time, the Government may have to think of re-constituting such Censor Boards. For instance, I have read captions of a certain film 'If I order'. It smacks something of the language or the policy of a dictator's Government, many actors and directors are involved in it. Hence, I would suggest that Government draws their attention to the dangers of such captions, of course, by using a most courteous language especially when we deal with actors and artistes and all these people. We have to treat them with the utmost courtesy. In fact, Prof. Mukerjee was also referring to the way in which we should treat the artistes. It is not enough merely paying a safe salary but we must give them a decent enough salary if not better. In the days of the Mughal period and even in the days before, the artistes were treated as equals if not superiors.

I would also like to mention about the cartoons that appear in the papers. There are many sexy items mentioned in them. These cannot go hand in hand with our family planning. The Government may curb this kind of literature and cartoons to the extent possible.

Finally I would like to say a word in appreciation of the Ministry for playing the devotional songs; they are doing it very well. A little more money must be spent on improving upon it. It creates an atmosphere of love. In these days when a number of people and parties—I don't exclude my party—are trying to spread hatred and hatred campaigns are going on, this is inevitable in a democratic set-up—let there be honest people to create an atmosphere of love and for this purpose, devotional songs play a great part. Here I would like to quote four lines of an old poem:

> "So many Gods, so many creeds,
> So many paths that wind and wind
> When just the act of being kind
> Is all this world needs."

**श्री ओंकार लाल बेरवा** (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में जो सुस्तियां हैं, उनकी आलोचना हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी इस मन्त्रालय की मन्त्री बनीं, तो हमने सोचा कि अब इसमें कुछ सुधार होगा, लेकिन सुधार होने के बजाये यह मन्त्रालय और बिगड़ता चला गया। मैं मन्त्री महोदय, श्री राज बहादुर, से यह निवेदन करूंगा कि अगर वह इस मन्त्रालय की तरफ़ विशेष ध्यान दें, तो अच्छा होगा। इस वक्त इस मन्त्रालय को जो राजनैतिक अखाड़ा बना रखा है, वह इस बारे में भी कदम उठायें और इस को राजनैतिक अखाड़ा न बनने दें।

कांग्रेस पार्टी के नेता के चुनाव के सम्बन्ध में आल इण्डिया रेडियो से जो प्रचार किया गया, उससे मालूम पड़ता था कि यह आल इंडिया रेडियो नहीं, बल्कि "आल इन्दिरा रेडियो" है। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इसमें जो भी गलतियां हैं, वह उनको जल्दी से जल्दी सुधारने की कोशिश करें।

**श्री इन्द्रजीत लाल लतरोजा** (जम्मू तथा काश्मीर) : आल इण्डिया रेडियो के प्रचार का हम पर असर नहीं होता है।

**श्री ओंकार लाल बेरवा** : यह ठीक है कि माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया,

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

था, लेकिन फिर भी वह प्रचार जारी रहा। उस चुनाव के सम्बन्ध में जो प्रचार किया गया था, उसके कारण इस को "आल इंडिया रेडियो" न कह कर "आल इन्दिरा रेडियो" ही कहना ज्यादा ठीक होगा। उस प्रचार को छिपाया न जाये। इस विभाग में जो खामियां हैं, उन को दूर किया जाना चाहिए।

मैं आप के सामने आल इण्डिया रेडियो की सुस्ती का एक उदाहरण देना चाहता हूं। रात के डेढ़, दो बजे ताशकन्द में शास्त्री जी की मृत्यु हुई। विदेशों के रेडियो स्टेशन रात के तीन चार बजे ही यह समाचार प्रसारित करने लग गए, लेकिन आल इण्डिया रेडियो से यह समाचार सवेरे पांच बजे प्रसारित किया गया, हालांकि उसका विशेष सम्वाददाता शास्त्री जी के साथ ताशकन्द गया था, लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं की कि इस समाचार को उसी समय प्रसारित किया जाये। इसके लिए मैं उनको जिम्मेदार ठहराता हूं।

राजधानी के एक महत्वपूर्ण पेपर ने लिखा है कि डायरेक्टर जेनेरल की जो नियुक्ति हुई है, वह भी नेताओं के आधार पर हुई है। एक दूसरे महकमे में, संगीत नाटक एकेडैमी में, इन की रिपोर्ट खराब थी, लेकिन फिर भी इन को यहां थोप दिया गया। इसका क्या कारण था? जब वह अनभिज्ञ थे और उनकी रिपोर्ट खराब थी, तो फिर उन को इसमें थोपना ग़लत बात है।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं, जिनका कम्युनिस्टों से सीधा सम्बन्ध है, जो कि बाहर के लोगों को सब बातें पहुंचा देते हैं।

**एक माननीय सदस्य : वे कौन हैं?**

**श्री ओंकार लाल बेरवा :** अगर इस की जांच की जायेगी, तो मैं यह सूचना दूंगा।

जिस वक्त पंजाब में झगड़ा हुआ, उस वक्त राज्य सरकार ने दो पत्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिया, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को यह नहीं कहा कि उन्होंने यह प्रतिबन्ध क्यों लगाया है और उन समाचार पत्रों के अधिकारों का हनन क्यों किया है। उन पत्रों ने कोई खास गुनाह तो नहीं किया था। यह एक बड़ी शर्मनाक घटना थी। यह तो अयूबशाही हो गई, जिसने पाकिस्तान में झगड़े होने पर पत्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। यह ग़लत बात है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

एक किताब है "लैज रोन्यूड" इसको छापने के लिए दो अफ़सर कलकत्ता गये हवाई जहाज से। इस किताब के लिए विदेशी पेपर का उपयोग किया गया। हमारे गरीब आदमियों को तो विदेशी मुद्रा के दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन इस किताब को छापने के लिए विदेशी मुद्रा खर्च की गई। इस किताब में श्रीमती इन्दिरा गांधी का भाषण तो था 26 जनवरी का, लेकिन फोटो उनकी शादी का छापा गया। यह कैसे चलेगा? क्या विदेशी मुद्रा का इस प्रकार उपयोग किया जायेगा? जयपुर अधिवेशन में वितरित करने के लिए इस किताब की पांच हजार कापियां छपवाई गई। अरे परमात्मा! यदि विदेशी मुद्रा के बारे में ऐसा अन्याय होता है, तो देश का उत्थान होना बहुत मुश्किल हो जायेगा।

1965 की डायरी को छापने का ठेका एक ऐसे ठेकेदार को दिया गया, जिसका टेंडर ही इनवैलिड था। इसमें पचास हजार रुपये का घोटाला हुआ है। बम्बई के उस ठेकेदार का टेंडर टाइम के बाद आया, लेकिन उसको एडमिट करके कोटेशन खोल कर रेट्स को आउट कर दिया गया। वह ठेका एक ऐसे ठेकेदार को दिया गया, जो कि "बी" क्लास ठेकेदार था, जबकि "ए" क्लास ठेकेदारों को यह काम नहीं दिया गया।

यह डायरी बहुत निकम्मी थी और 1966 की डायरी के मुकाबले में रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक थी। यह डायरी विदेशों में बांटने के लिए भेजी गई, लेकिन ट्रान्सिट्स के हैड आफिस से यह रिपोर्ट आई कि यह डायरी रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है, इसको विदेशों में नहीं भेज सकते हैं।

एक एलबम इस खयाल से छापी गई कि उस को न्यूयार्क के मेले में बांटा जायेगा। बिल मन्त्रालय ने कहा कि उस के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं है। डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये एलबम बहुत बिकेगी—एक-एक डालर में बिकेगी। इस प्रकार उस एलबम की पांच हजार प्रतियां छपवाई गईं। लेकिन उसकी पचास प्रतियां भी नहीं बिकीं और इस प्रकार पच्चीस हजार रुपये का नुकसान हो गया। जब ये एलबम बाजार में नहीं बिकती हैं और विदेशों के लोग उस को लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर डायरेक्टर साहब उस को अपने घर में रख लें। इस तरह के कामों में विदेशी मुद्रा खर्च करना और देश को गुमराह करना बहुत बुरी बात है। अभी सन् 1966 की डायरी उसी ठेकेदार को दी गई, जिस ठेकेदार का सन 1965 में नाम तक नहीं लिया गया था, जिसको राष्ट्रपति ने इनाम दिया था, उसका नाम तक नहीं लिया। सन् 1965 के डायरी छपवाने के मामले को दबाने के लिये उसी ठेकेदार को बुलाया गया। अब आप दोनों डायरियों को मिला कर देखें कि कितना अन्तर है। वहां आफिस में जब टाइम से डायरी नहीं बनी, तो उसके ऊपर 80 हजार की पैनेल्टी डाल दी गई, इस पर उस क्लर्क को नहीं से ट्रांसफर कर दिया और इस तरह से उस मामले को रफा-दफा करके मामले को गुम कर दिया। यदि प्रसारण के महकमे में इस तरह से विदेशी मुद्रा का सत्यानाश किया जाय, तो बतलाइये इस तरह से कैसे चलेगा।

अब मैं विविध भारती को आपके सामने लेता हूं। विविध भारती में रोजाना वही घिसे-पिटे गाने आते हैं और दिन में तीन-तीन दफा एक ही आदमी के नाम लेकर गवाये जाते हैं, जैसे रिकार्ड कर रखा है। सुबह किशन पटनायक, दोपहर को किशन पटनायक और फिर शाम को किशन पटनायक, तीन तीन दफा जैसे रिकार्ड कर रखा है...

**श्री राज बहादुर** : गाना कौनसा है, वह तो बतलाइये।

**श्री ओंकार लाल बेरवा** : विविध भारती के अन्दर इस तरह की बातें होती हैं। आज हमारे व्यापारियों का बहुत ज्यादा पैसा सीलोन रेडियो पर खर्च होता है, मैं चाहता हूं कि वह पैसा विविध भारतीय को आये और सीलोन रेडियो को भेजे जाने वाले साढ़े एडवर्टिजमेण्ट बन्द किये जायं। क्योंकि इस तरह से हमारे देश का बहुत काफी पैसा विदेश को चला जाता है। लेकिन हमारे मन्त्री जी को अंग्रेजी से ज्यादा प्यार है, है इसलिये विदेशों से ज्यादा प्यार है...

**एक माननीय सदस्य** : अब वालों को नहीं है।

**श्री ओंकार लाल बेरवा** : अब वालों को इसमें सुधार करना चाहिये।

इस समय जयपुर और बीकानेर के रेडियो स्टेशन मिल कर बोलते हैं, बीकानेर और उदयपुर के रेडियो स्टेशन मिल कर बोलते हैं, तो मैं मन्त्री महोदय से पूछता हूं कि कोटा इसमें क्यों छूट जाता है। कोटा में हाड़ौती भाषा का रेडियो स्टेशन होना चाहिये। हाड़ौती भाषा हमारे राजस्थान की एक मशहूर भाषा है, उसका गाना सुनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। इसलिये जयपुर और कोटा का स्टेशन मिला कर उसका प्रसारण किया जाय।

अब मैं हिन्दी के बारे में थोड़े से आंकड़े बतलाना चाहता हूं। जब हमारे नये मन्त्री

[श्री ओंकार लाल बरवा]

जी आये और उन्होंने मन्त्री बनते ही हिन्दी के जितने भी टेलीप्रिन्टर्स थे, उनको बन्द कर दिया और उनसे कह दिया कि अगर तुम नौकरी करना चाहते हो तो तुम्हें अंग्रेजी वालों से 20 रु० कम मिलेंगे, इस तरह से हिन्दी का उत्थान हो रहा है क्योंकि इनको अंग्रेजी से ज्यादा मोह है । मैं इस तरह के भ्रष्टाचार के बिल्कुल विपरीत हूं ।

अब मैं आपको पुस्तकों के प्रकाशन के बारे में बतलाना चाहता हूं । सन् 1960 से 1965 तक 4,492 पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिनमें 2,572 अंग्रेजी की हैं । सिर्फ 691 हिन्दी में और 768 अन्य भाषाओं में प्रकाशित हुई । सन् 1959 से 1965 तक कोई तरक्की हिन्दी के अन्दर नहीं हुई । हिन्दी में 1959 पुस्तकों से घट कर 728 रह गई, मराठी में 358 से घट कर 218 रह गई, गुजराती में 190 से घट कर 165, तामील में 268 से घट कर 193, तेलगु में 142 से घट कर 108, कन्नड में 161 से घट कर 74, उर्दू में 179 से घट कर 54 और बंगला में ३४८ से घट कर २ ६, लकिंद इसके मुकाबले में अंग्रेजी के प्रकाशन में पांच साल में 1893 से बढ़ कर 3272 हो गई । यह कितने शर्म की बात है, हमारी हिन्दी के साथ यह कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है ।

अभी मैं यहां पर चन्दा समिति की बातें सुन रहा था टेलीविजन के बारे में । टेलीविजन के लिये बहुत से मेम्बरों ने बहुत तारीफ़ की है, लेकिन मैं उसका विरोध करना चाहता हूं । आज देश की 80 प्रतिशत जनता भुखमरी की शिकार है, क्या हमारी जनता का टेलिविजन के द्वारा पेट भरा जायगा । हमारे देश की जनता को आज अनाज और खाद नहीं मिल रही है लेकिन दूसरी तरफ़ आज टेलिविजन लगाया जा रहा है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इस देश को खाद्य में निर्भर नहीं बनाया जाता, तब तक ऐसी योजनायें न बनाई जायें, जिनसे गरीब जनता पर असर पड़े । इसका लाभ कुछ उच्च अधिकारियों को, ए और बी क्लास अधिकारियों को ही होगा, लेकिन जो बाकी की गरीब जनता है, उसको इससे कोई लाभ नहीं पहुंच सकेगा ।

मैं एक बात और रखना चाहता हूं । दिवाकर कमेटी की रिपोर्ट जो कि छोटे अखबारों के बारे में है, चन्दा कमेटी की रिपोर्ट से पहले आई थी, लेकिन चन्दा कमेटी की रिपोर्ट को तो आप जल्दी लागू करने जा रहे हैं, जबकि दिवाकर कमेटी की रिपोर्ट को आपने रद्दी की टोकरी में डाल रखा है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि उस कमेटी की रिपोर्ट पर शीघ्र अमल किया जाय और छोटे पत्रकारों को प्रोत्साहन दिया जाय, ताकि वे गांव-गांव में हर जिले में, हर गांव में किसानों के पास पहुंच सकें ।

एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं । गर्मी के दिनों में किसानों का जो प्रोग्राम होता है, वह उस समय होता है जब किसान खेत में होता है । इसलिये उसको वह समय एलाट किया जाय, जबकि किसान घर पर आ जाय । जिस समय किसान खेत पर होता है, उस समय उसके प्रसारण से कोई फायदा नहीं है, उस समय पंचायत समिति के केन्द्रों में रेडियो बजा करे, उससे कोई लाभ नहीं होगा, इसलिये उसके समय में परिवर्तन किया जाय ।

आज प्रसारण के अन्दर जितना भी भ्रष्टाचार है, जो राजनीतिक अखाड़ों के शिकार बने हुए हैं, उन भ्रष्टाचारों की जांच की जाय ।

**श्री जीनारायण दास** (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मन्त्रालय सूचना और प्रसारण का एक ऐसा विभाग है, कि जिसके काम पर हिन्दुस्तानी प्रजातन्त्र का सफल संचालन और उसका अच्छा प्रबन्ध निर्भर करता है । प्रजातन्त्र के सफल संचालन के लिये शिक्षित और जाग्रत लोकमत की आवश्यकता होती है । यह बात हम लोगों

को मालूम है कि 15 वर्ष के स्वराज्य के बाद भी अभी हमारे देश में पढ़े-लिखे लोगों की तादाद बहुत ही कम है । ऐसी अवस्था में आल इण्डिया रेडियो एक साधन है कि जिसके जरिये हम हिन्दुस्तान के उन करोड़ों भाइयों तक प्रजातन्त्र के सम्बन्ध की बातें पहुंचा सकते हैं, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं या जिन्हें हमने अभी तक पढ़ा लिखा नहीं बनाया है । इस दृष्टि से जो-जो काम इस प्रजातन्त्र के सफल संचालन और शिक्षित और जाग्रत लोकमत के लिये चाहिये, वह काम इस मन्त्रालय के जिम्मे है । लेकिन बावजूद इस बात के लिये धीरे-धीरे इस विभाग का विस्तार होता जा रहा है और जिन-जिन बातों की आवश्यकता मौलिक या गौणरूप से है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिया जाने लगा है । लेकिन अभी भी जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह जो प्रचार विभाग है, या प्रसार विभाग है, यह हिन्दुस्तान की जरीब जनता तक या जो सरकार की बातें पहुंचाने में असमर्थ है या लोकमत को शिक्षित करने के लिये जिन बातों की आवश्यकता होती है, उन बातों के प्रचार में अभी तक समर्थ नहीं हो सका है । उसका एक कारण तो यह है जैसा कि इस सदन में स्पष्ट मालूम पड़ता है कि अभी भी हम अंग्रेजी के प्रचार के लिये ज्यादा समय देते हैं । हिन्दुस्तान में बहुत सी भाषायें प्रमुख भाषायें हैं, 14–15 के लगभग हैं, हो सकता है कि राज्य सरकारों के जरिये स्थानीय भाषा में जनता तक विचार पहुंचाये जाते हैं, लेकिन जहां तक केन्द्र सरकार का ताल्लुक है, विशेष तौर पर अंग्रेजी का ही महत्व है और और जैसा कि अभी हमारे भाई ने कहा कि जब पुस्तकों का प्रकाशन होता है, या पुस्तिकाओं का प्रकाशन होता है तो केन्द्र सरकार ज्यादा से ज्यादा पुस्तक अंग्रेजी में ही प्रकाशित करती है । जहां हमारे देश में अंग्रेजी बोलने वाले 100 में से 2 आदमी भी नहीं होंगे, ऐसे प्रचार से हिन्दुस्तान की जो असली जनता है, उसके विचार नहीं बदल सकते ।

हमारे कई माननीय सदस्यों ने टेलीविजन की चर्चा की है । मैं भी इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं । धनी देशों के लिए, या मनोविनोद के लिए और शिक्षा के लिए भी टेलीविजन की आवश्यकता हो सकती है । लेकिन हिन्दुस्तान की गरीब जनता का पैसा हम लेते हैं और टेलीविजन अगर जारी हो जायेगा तो उसका लाभ बहुत थोड़े से लोगों को शहरों में ही मिलेगा । इसलिए अभी समय नहीं आया है टेलीविजन जारी करने का । अभी जरूरत इस बात की है कि रेडियो का जो प्रचार है उस प्रचार को व्यापक बनाया जाये और उसको व्यापक बनाने के लिए कम्युनिटी सैट हर गांव में दिये जायें । इस कम्युनिटी सैट्स के प्रोग्राम को आपको चाहिये कि आप बढ़ायें । अभी भी हिन्दुस्तान में छः लाख गांवों में से बहुत से गांव ऐसे हैं जहां एक भी रेडियो है नहीं । मैं समझता हूं कि टेलीविजन का प्रचार करने के बजाय मंत्री महोदय गांवों के अन्दर कम्युनिटी सैट देने का प्रयत्न करें । कोई भी गांव ऐसा नहीं रह जाना चाहिये जिस में कम से कम एक कम्युनिटी सैट न हो ताकि रेडियो के द्वारा चाहे वह आल इंडिया रेडियो हो या दूसरा रेडियो हो जो प्रचार होता है उस प्रचार को हर गांव में सुना जा सके । मैं टेलीविजन के प्रोग्राम को बढ़ावा देने की सख्त मुखालिफत करता हूं । मैं चाहता हूं कि इसको आगे प्रोत्साहन न दिया जाये । जितना है उतने को ही रखा जाये । उससे आगे इसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ।

•

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि 15–16 बरस स्वराज्य आये हुए हो गये हैं लेकिन अभी तक हमारे देश में जो अखबार चलते हैं वे बहुत ही सीमित लोगों के अखबार हैं । कहा जाता है कि बोलने की और लिखने की स्वतंत्रता हम ने दी हुई है । यह ठीक है । लेकिन जो अखबार चलते हैं बावजूद इस बात के कि हम ने बहुत प्रयत्न किया है फिर भी अभी तक जो अखबारों के मालिक हैं

[श्री श्रीनारायण दास]

उनके सम्पादकों पर उनका ही असर अधिक होता है। सम्पादक का असर नहीं होता है। मैं समझता हूं कि जैसा कि सुझाव दिया है छोटे-छोटे अखबारों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। साथ ही साथ अखबारों के क्षेत्र में कोऑपरेटिव का विस्तार होना चाहिये। कोऑपरेटिव ढंग पर अखबार चलाने को जितना भी प्रोत्साहन सरकार दे सके, सरकार को देना चाहिये ताकि ऐसे अखबारों का सृजन हो जोकि सचमुच में निर्भीक और स्वतंत्र हों और निडर हो कर वे शासन के सामने जो उचित बात है, रख सकें, उसका प्रचार कर सकें। एकाधिकार की जो प्रवृत्ति इस क्षेत्र में पाई जाती है, उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिये।

हमारे देश में पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए इस विभाग के अन्दर सरकार ने प्लान पब्लिसिटी का प्रबन्ध किया है। लेकिन बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि प्लान पब्लिसिटी का जो महकमा है वह भारत के पांच छः लाख गांवों में अपनी बात का प्रचार पूरे तौर पर नहीं कर सका है। मैं इस बात को मानता हूं कि पैसे का अभाव है और उसकी वजह से इस काम को उस हद तक नहीं किया जा रहा है जिस हद तक किया जाना चाहिये। हाल ही में एक कमेटी बिठाई गई थी। उस कमेटी ने सुझाव दिया है कि जहां तक सरकार उन महकमों को मजबूत कर सकती हो, उसको मजबूत करने का प्रयत्न करना चाहिये। लेकिन साथ ही जो गैर-सरकारी संस्थायें बहुत दिनों से प्रचार का काम जनता में करती आई हैं उनको भी पूरा बढ़ावा दिया जाना चाहिये। एक ऐसी संस्था कायम की जानी चाहिये जिसके जरिये से जो-जो गैर सरकारी संस्थायें बहुत दिनों से लोकमत का सृजन या लोक मत को शिक्षित करने का काम कर रही हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया जा सके।

हमारे देश में जो समाचार समितियां हैं उन में ज्यादा तर बढ़ावा पुरानी समाचार समितियों को ही सरकार की ओर से दिया जा रहा है। हिन्दुस्तान समाचार समिति अभी थोड़े दिन हुए कायम हुई है। उसको सरकार को जहां तक हो सके अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिये। अगर कोई नई समाचार ऐजेंसी बनने के लायक है तो उस समाचार ऐजेंसी को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

मैं उत्तर बिहार से आता हूं। वह एक पुराना मिथिला प्रदेश है। वहां के लोगों की बहुत दिनों से रेडियो स्टेशन की मांग चली आ रही है। वे चाहते हैं कि दरभंगा में एक रेडियो स्टेशन खोला जाये। दरभंगा मैथिली का केन्द्र है। यद्यपि हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है लेकिन लगभग एक करोड़ लोग मैथिली बोलते हैं। उनका अलग साहित्य है और एक तरह से अलग ही संस्कृति है। दोनों में अपनी-अपनी विशेषतायें हैं। कई बार इस बात के लिए सवाल उठाया गया है। जनता की मांग है कि उत्तर बिहार में दरभंगा में एक रेडियो स्टेशन खोला जाये। वहां के लगभग एक करोड़ लोगों की यह मांग है। मैं चाहता हूं कि उनकी इस मांग को पूरा किया जाये। अगर ऐसा एक स्टेशन खोला जायेगा तो बहुत ही यह कारगर होगा।

एक काम के लिए मैं आप को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उसका मैं समर्थन करता हूं। इस विभाग के काम का जो एक मौलिक साधन है उसके सम्बन्ध में अन्वेषण और अनुसंधान करने के लिए इंस्टीटयूट आफ मास कम्युनिकेशन नाम की जो संस्था खोली गई है, उसको धीरे-धीरे बहुत व्यापक बनाया जाना चाहिये। मालूम नहीं उस संस्था का संचालन करने वाले अभी तक भी विदेशी हैं या केवल हिन्दुस्तानी ही उस संस्था का संचालन करते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा

प्रयत्न होना चाहिये कि उस संस्था के संचालन के लिए ज्यादा से ज्यादा हिन्दुस्तानियों को तैयार किया जाये ताकि प्रचार के जितने साधन हैं यह संस्था उनके सम्बन्ध में पूरा अन्वेषण तथा अनुसंधान कर सके और केन्द्र या राज्यों के जो कर्मचारी प्रचार कार्य में लगें उनको शिक्षित कर सके और हर तरह के रिसर्च और ट्रेनिंग और दूसरे प्रकार के काम हो सकें ।

फिल्में जो हैं वे शिक्षा के लिए बहुत कारगर हो सकती हैं । अभी तक जो फिल्मों का निर्माण किया है मैं समझता हूं वह कम नहीं है । फिर भी स्कूलों और कालेजों में फिल्मों का जितना उपयोग होना चाहिये अभी तक नहीं हो सका है । मेरा सुझाव है कि ऐसी वृहद् लाइब्रेरी फिल्मों की होनी चाहिये जिस लाइब्रेरी से यूनिवर्सटीज और स्कूलों आदि के लिए फिल्में ली जा सकें और विद्यार्थियों को उनके जरिये से शिक्षा दी जा सके । इस बात की भी आज बड़ी आवश्यकता है ।

जहां तक अश्लील फिल्मों के प्रदर्शन का सम्बन्ध है इस बारे में हमारे देश में दो मत हैं । सेंसर बोर्ड का जहां तक सम्बन्ध है वह संविधान के अन्दर काम करता है । बहुत से लोग हैं जिन में हमारे आचार्य विनोबा भावे जी भी हैं जो यह कहते हैं कि वह जिस तरह से फिल्में प्रदर्शित करने की मंजूरी देता है वे फिल्में ऐसी होती हैं जिन से कि हमारे देश में लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है । कई बार इस प्रश्न को उठाया गया है । तत्कालीन जो मंत्री महोदय थे उन्होंने कहा था कि संविधान के अन्दर जितनी हम रोक लगा सकते हैं उतनी लगाते हैं लेकिन और रोक लगाने से हमें संविधान रोकता है, हमारे रास्ते में बाधक होता है । मैं मानता हूं कि यह बात कठिन है क्योंकि इस देश में दो तरह के मत हैं । कुछ लोग हैं जो यह चाहते हैं कि बिल्कुल किसी प्रकार का नियंत्रण फिल्मों पर न रहे । जो फिल्में बनाई जायें उनको जहां तक हो सके—अगर किसी की नजरों में अश्लील भी हों—प्रोत्साहन देना चाहिये, मंजूरी दे देनी चाहिये । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए एक कमेटी बनाई जाये जो निर्णय करे कि फिल्मों के सेंसर में कौन-कौन क्राइटीरिया होना चाहिये, कौन-कौन सी बातें इस्तेमाल होनी चाहियें ताकि देश का वातावरण अच्छा हो सके और खास तौर से जो बच्चे हैं स्कूलों के और कालेजों के जो लड़के हैं उन लोगों पर खराब असर न पड़े । खराब प्रभाव डालने वाली फिल्मों का निर्माण नहीं होना चाहिये ।

इस मंत्रालय के मंत्रीगण बदलते रहे हैं । अब जबकि इन माननीय मंत्री जी के हाथ में यह मंत्रालय है तो जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है मैं भी उनका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि उनकी देखरेख में यह मंत्रालय अधिक से अधिक जनता के फायदे के लिए काम करेगा । जैसे मैंने कहा है रेडियो सुनने के लिए अधिक से अधिक पांच वर्ष के अन्दर-अन्दर कोई ऐसा गांव नहीं बच रहना चाहिये जहां कि कम्युनिटी सैट न हो । टेलीविजन के प्रोग्राम को अगर कम करना पड़े और उसको रोकना पड़े तो मैं समझता हूं कि उसको रोक देना चाहिये । टेलीविजन के प्रोग्राम को ज्यादा बढ़ावा देना हिन्दुस्तान के गरीब करदाताओं की दृष्टि से अच्छा नहीं होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूं ।

Shri Sezhiyan (Perambalur): Mr Deputy-Speaker, the Ministry of Information and Broadcasting is concerned with the important media of mass communication, viz., radio, press and film publicity. As pointed out in a recent report of the Chanda Committee, available facilities in this country are very meagre in regard to these media, because as against the

[Shri Sezhiyan]

minimum standard set by UNESCO of at least 50 radio sets, 100 copies of daily newspapers, 20 cinema seats and 20 TV sets per each unit of 1,000 people, we have in India only 8 radio sets, 11 copies of newspapers, 6 cinema seats and no TV at all.

We have a long way to go, but the pity is that even the meagre facilities in our country have not been put into proper use in proper shape.

Regarding the programmes of AIR, many speakers preceding me have referred to them. The programmes are invariably insipid and they do not reach the people at large. As far as the language distribution is concerned, it is very heavily biassed. As I pointed out even last year, if we take the news items prepared in various units of regional languages, that is, the national languages, the Hindi unit has been staffed properly, but the other language units have not been given as much of preference as is given to the Hindi unit. For the Hindi language unit, there is a grade I officer, there are three grade II officers, there are translators, there are announcers, stenos; even reporters have recently been appointed. But if we take the other units like Tamil or Telugu, there is only one person who is the translator as well as announcer. There is no grade one or grade two officers there. I am not grudging the position of Hindi. The Hindi bulletin should come our properly, but the same facilities should be given to the other languages also, and they should not be given a stepmotherly treatment. Millions of people are there in the country whom you have to reach through those languages. India is a vast country where 77 per cent are illiterate, and 80 per cent live in rural areas. Therefore, if you want to reach them, you should go to them in the language which they speak and understand. I do not want English to predominate over our mother tongues, but the regional languages should be given a fair deal.

**15 hrs.**

The Vivid Bharati in our parts is called the Vedanai Bharati, i.e., the miserable Bharati.

**Shrimati Yashoda Reddy** (Kurnool): Something which gives you more pain than pleasure.

**Shri Sezhiyan:** That is a Tamil word. Out of 13 or so in a day, about 1½ hours are given for all the four languages of the South, Tamil, Telugu, Malayalam and Kannadam. They have been put together as Madrasi languages as they call it. And even there, all the announcements are made in Hindi. If you tune to hear some film song or light music, the introduction is always in Hindi, though they may not even know what is sung. I fully remember that there was a song from the Tamil film *Palum Pazhamum* which means fruit and milk, but the versian given by the Hindi announcer was *Puzhum Palam*, i.e., a damaged bridge. Even the little bridge that we have among various regions is being damaged by the Hindi announcers. I say this because we should have a clear policy in making these announcements. That is why in our parts people, and even in Delhi, those who come from the southern parts, tune Radio Ceylon because in the two hours allotted there, they do not introduce Sinhalese, though that may be their State language. In Tamil programmes, the announcement is made in very good Tamil. In my own land of birth, the announcement is not made in my language, but in Singapore and Ceylon they give it in very good Tamil.

The Chanda Committee report on television is very categorical in this regard, as in para 135 they say:

> "We should only stress now that the language used in the broadcasts should be what people themselves use in the viewing areas."

I can also show the predominant bias shown in favour of Hindi and the step-motherly treatment meted out to the other languages.

**An hon. Member:** What about English?

**Shri Sezhiyan:** The first point is that English should not have a place over any mother tongue in the country, and it is an alien language to me, I accept it.

**Shri Balmiki** (Khurja): Hindi has got a place in the country.

**Shri Sezhiyan:** It is your version, but Hindi is also alien to me. As far as the radio goes, the announcements and the news items should be in the languages of the people for whom they are meant. The regional languages should be given preponderence. When a news item comes from Trichy or Madras, let it be 100 per cent Tamil; if it comes from Vijayawada, let it be 100 per cent Telugu.

For Vivid Bharati they have got 26 centres for transmission, and throughout India it is given in Hindi. As Shri Ansar Harvani was saying, that Hindi is not understood by many people in Hindi area itself. Then, how can we understand it? That is why Vividh Bharati should be decentralised and it should be done in the local language.

I now come to the Annual Report for 1965-66 of the Ministry. At page 29 of the Ministry's Report, it is said:

> "Hindi Unit. All Hindi news bulletins are now compiled independently out of the basic news material received in the News Room. They are thus no longer a mere translation of the English bulletins. Some of the items are based on original despatches filed by reporters in Hindi."

Cannot the same facility be given to the Tamil and Telugu units?

At page 65 there is a para on Hindi Services, but no other service is mentioned.

At page 77, on Emergency Publications, it is said:

> "Up to the 31st December, 1965, the Division had brought out 16 pamphlets in English, 11 in Hindi and 10 in Urdu."

I do not know what happened to the other languages. Probably the emergency is only for the Hindi-speaking areas. In that case, I would advise them to lift the emergency for the non-Hindi areas.

At page 79 in the Chapter on Publications Division, it is written:

> "The Division is giving special attention to the publication of books and pamphlets in Hindi."

But why not the same facilities be given to the other languages?

Shri Mukerjee referred to the collected works of Mahatma Gandhi. It is being compiled in English and in Hindi. Why not in other languages? We would also like to read.

On page 80, it is mentioned that only three journals, viz., Ajkal (Hindi), Anjal (Urdu) and Bal Bharati (Hindi) are published on behalf of the Ministry of Information and Broadcasting. I do not think the Ministry is meant only for the Hindi States. It should be means for the other States also. Why don't you publish magazines in other languages for the other States?

At page 85 in the chapter on Song and Drama Division, it is stated:

> "Departmental Drama Troupes: The two Departmental Drama Troupes of the Division gave 241 performances during the year 1965 as against 222 in the preceding year."

The break-up is as follows:

| | |
|---|---|
| Central Drama Troupe .. | 103 |
| Departmental Drama Troupe for U.P. and Bihar .. .. | 138 |
| Total .. | 241 |

[Shri Sezhiyan]

There is no departmental drama troupe for Tamil Nad or Telugu areas. Only for U.P. and Bihar they are catering.

In the same chapter, at page 86, under the heading *Ballot* it is mentioned that 30 performances of ballets, Krishna Leela and Ram Leela, were given in Madhya Pradesh, Maharashtra, U.P. and Bihar. There is no ballet prepared for other areas and languages.

Again, at page 86, on Emergency Publicity, it is stated:

> "With the onset of Pakistani aggression, the Division completely reoriented its activities and went in for intensive publicity for defence, national preparedness, communal harmony and national unity. ... prepared special composite programme of topical interest entitled *Ham Tum Aur Woh.*"

I do not know how it is to be pronounced. Please excuse me. I am reading from the version in English. No disrespect is meant for Hindi.

At page 101, the P.I.B. releases in Indian languages during 1965 are given as under:

| | | |
|---|---|---|
| Hindi | .. .. | 7,747 |
| Telugu | .. .. | 1,936 |
| Tamil | .. .. | 4.511 |

I do nothing against the number of Hindi releases, probably more should be issued, but why are you grudging other people? Can't they read if you have releases in their own languages? They should also know what is happening in our Government, what is happening to the country.

Pages 90-91 give tables of classified and display advertisements in the various language pepers. The figure for Hindi is Rs. 9,97,183, while for Tamil it comes to Rs. 2,53,201 and for Kanarese Rs. 1,36,657. But those papers should also exist.

**Shri Kishen Pattnayak** (Sambalpur): You read the figures for English.

**Shri Bhagwat Jha Azad** (Bhagalpur): Let us know the figures for English also.

**Shri Sezhiyan:** I have not taken them. English is not my language, I do not bother about it. You may throw it back to England if you don't need it, I am pleading for my own language.

**Shri Bhagwat Jha Azad:** We are very happy to hear.

**Shri Sezhiyan:** Then, regarding the well known item *Today in Parliament*, I want to say something. I am not going into the merits or demerits of it. There are many complaints from the other side also, but I am not going into that question. I want to raise a question on a matter of principle. Previously this item *Today in Parliament* was prepared by a holetime employee of A.I.R., but now it has been given as a part-time job to a person who is the permanent representative of a foreign news service. I understand that from that foreign news service he is receiving about Rs. 2,000, and he is also receiving Rs. 1,000 from A.I.R. for his part-time work. On a question of principle, and from the point of view of security also, is it desirable to allow a person who is connected with a foreign news agency to enter into the portals of A.I.R. where most of the monitoring services ars working, many news items may be coming there which are available to him who is working only part-time here and is permanently attached to a foreign news service? I say, it is highly objectionable.

**Shri Bhagwat Jha Azad:** What is that agency?

**Shri Seshiyan:** It is a French news agency. Whatever it may be, there is bound to be bias and divided loyalty when he works fulltime in a foreign news agency and only part time in the A.I.R. We do not have dearth of qualified persons and we are paying him a thousand rupees. Previously there was a full-time officer. I am not here to say anything against the calibre of the person. But as a matter of principle and from the point of view of security, I am asking whether this is desirable. It may not be desirable.

I shall now refer to the grants given by the ministry for plan publicity. It is only on Saturday I got the report of the evaluation committee on plan publicity. Upto the end of 1963, this ministry had given a total of Rs. 30.18 lakhs to voluntary organisations; of this Bharat Sevak Samaj has received Rs. 28.78 lakhs, over 95 per cent. Even in this report, it is said that the work done by the B.S.S. has not been satisfactory. Some of the publications are good both in their content and get-up "but most of them are far below standard and brought out without proper consideration and care." At another place they say:

> "Our field studies and the discussions that we had with a large number of non-official workers have, however, confirmed the view that, besides the Bharat Sevak Samaj, there are available in the country a large number of institutions and dedicated non-officials who, if provided with adequate stimuli, would also be able to contribute substantially to generating better understanding amongst the people of the country's needs, its plans of development and other nation-building programmes."

If the government is determined to root out corruption, they must attend to this first. Last year, we had the P.A.C. report on the Bharat Sevak Samaj. If you want to save Bharat, you must abolish the Bharat Sevak Samaj and avoid all the irregularities that were pointed out.

**Shri Hanumanthaiya** (Bangalore City): Sir, I wish to bring to the notice of the hon. Minister only one point. I am making only a one-point speech today. On page 28, last para, the report says that the A.I.R. news bulletins have been given a new orientation in quality, content and format. The description is no doubt very alluring. If you listen to the news bulletin, that effect is not produced on the human mind. News bulletin is a *news* bulletin and not a speech bulletin. Anybody who listens to this item is inflicted with speeches of the Ministers, President, Vice-President and the Prime Minister. It has become almost a ritual. First comes the President's speech; then comes the Vice-President's then the Prime Minister's speech and then the other Minsters' speeches. I do not know what is going to happen under your aegis. But so far as broadcasting Ministers were concerned, it was a special privilege to mention his speech wherever he spoke. It was something like an Indian Airlines personnel having a free ride in the aircraft. We are helpless. We read the speeches of either the President or the Vice-President in newspapers. Can we find news from the speeches of President or the Vice-President? We must be united, that is news; we must be honest, that is news; we must fight aggression, that is news. In no other country would such a thing be tolerated. It is one of the disadvantages of this huge machinery being at the disposal of the government. Officials want to propitiate ministers; ministers want to propitiate the Prime Minister and the Prime Minister wants to propritiate, I do not know, whom. This kind of propitiation in the news bulletin does not correspond to the statement of what is called 'improvement in orientation, in quality and content'. I am a Member of Parliament and I realise the difficulties of ministers, deputy ministers, cabinet ministers. It is very difficult in these days, in this set-up to think independently. If some one high up is displeased he may not be sure at all of being in office. Therefore, I got up

[Shri Hanumanthaiya]

to protest vehemently and publicly that these news bulletins must be purged of their speech content. Not that I am jealous of these ministers or the Vice-President or the President. You have got the radio news-reel. Have it for one hour and repeat all the speeches made by these dignatories every day. I have no objection. Even if you want to repeat the homilies very day, have them all. You have Vivid Bharati; have Mantri Bharati; get it all day repeated so that those people who want to have it . . .

**Shri Bhagwat Jha Azad:** It should be Bharat Mantri.

**Shri Hanumanthaiya:** All right. But news bulletin must be news. The speeches must come under separate heading. You may have to please the ministers. But at the same time make the news bulletin correct, so that people may know what the news is and what the speech is.

Secondly, this All India Radio in Delhi unwittingly has been converted into a regional station for north Indian or Hindi-speaking area. You must remember that A.I.R. belongs not merely to this area but to the whole of India; it should really be a national radio. Please see your own figures at page 30. You say that there are at present 51 correspondents located in different parts of the country who are regularly feeding the central as well as regional organisations. You have a costly machinery of 51 correspondents. What is the time that you give for the State news in the bulletin? It is legitimate to ask that out of 15 minutes, let the central news get about ten minutes and at least five minutes be given for all the sixteen states. I have no time now to quote examples. Very important things are happening in the states but they are not given publicity, but anything that happens in Delhi region which is ordinary and of a routine type, homily-making speeches of Ministers etc., is inserted in the news. News must be news; all-India news consisting of central news and State news. If this reformation is done everybody would be grateful to the two ministers who have come on the scene. I know both of them; they are very sincere and able people. I am happy that they have been given this responsibility. If you cannot advise your higher-ups, please tell them that they must be saved from this odium that everybody forms in his mind after hearing the news bulletins. Whether it is the President or any one of the Ministers, speeches must be scrupulously excluded unless there is some announcement made which is in the nature of news. As you know, President cannot make any announcement which is in the nature of news. The ideas of the Minister cannot ordinarily be an announcement which is in the nature of news. Sometimes the Prime Minister may make such an announcement. I can see that. The officials who edit must be really impartial. They must be really men of independence and grit and not people whose only philosophy in life is propitiation of the higher-ups. They must edit these fifteen-minute news items in the real spirit of news and not in the spirit of propitiating their superiors.

**श्री किशन पटनायक** : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल को पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा दो बार अयोग्य घोषित किये जाने के बाद भी रक्खा गया है या अगर उन्होंने देशी भाषाओं को कुचलने के लिए कोई योजना बना रक्खी है तो उस पर इस वक्त मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन अंग्रेजी भाषा के द्वारा इतना जहर फैलाया जाता है कि उसकी एक मिसाल मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। 24 तारीख को प्रधान मंत्री ने देश को संदेश दिया। हिन्दी में भी दिया और अंग्रेजी में भी दिया। हिन्दी में तो ठीक था लेकिन अंग्रेजी में

गलती हुई। उनके अंग्रेजी संदेश में से मैं एक वाक्यांश पढ़ देना चाहता हूं :—

"There came violence in Bengal, Punjab and far away Mizo Hills."

अब यह फार अवे मीजो हिल्स का क्या मतलब होता है? आकाशवाणी सारे भारत की है, प्रधान मंत्री सारे भारत के हैं और अगर किसी इलाके के बारे में हिन्दुस्तान में यह कहा जाता है कि फार अवे मीजो हिल्स तो मीजो हिल्स के लोगों के मन में क्या छाप उसकी पड़ेगी?, हिन्दी में क्योंकि वह मातृभाषा है इसलिए गलती नहीं हुई लेकिन चूंकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है, गुलामों की भाषा है इसलिए इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा जहर उगला गया। मंत्री महोदय जरा विचार करें कि इस वाक्यांश का हिल पीपुल पर कैसा असर पड़ा होगा? मैं इस अवसर पर उनसे अनुरोध करूंगा कि यह गलती स्वीकार की जाय, मंत्रालय माफी मांग ले और आकाशवाणी में संशोधन भी प्रसारित करा दें और अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत आभारी रहूंगा।

इसके बाद मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आकाशवाणी के नौकरशाही के लोग किस तरह आकाशवाणी के कलाकारों का खून चूसते हैं और कलाकारों को दबाये रखने के लिए उनको तरक्की न देने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं।

मेरे पहले श्री हीरेन मुकर्जी ने चतुर लाल की मिसाल दी। मैं चतुर लाल के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें कहूंगा जोकि आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। हिन्दुस्तान

15:23 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

के अनोखे वाद्ययंत्र तबले को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान दिलाने में चतुर लाल का बहुत हाथ रहा। यह चतुर लाल मर गया 39 साल की उम्र में। जबकि आकाशवाणी के नौकरशाही लोगों को 2000 रुपये की तनख्वाह मिलती है चतुर लाल को 20 साल की नौकरी के बाद 300, 350 रुपये का वेतन मिलता था। उसके मरने के बाद न तो उसकी फैमिली को अभी तक ग्रेजुएटी मिली है और न ही अभी तक कोई पैंशन का इंतजाम हुआ है। मुझे इत्तिला है कि उसके परिवार की हालत अच्छी नहीं है और इस चतुर लाल को जिसको कि अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर एक बड़ा कलाकार माना जाता है आकाशवाणी के नौकरशाही के लोग ए० क्लास का भी नहीं मानते, बी० क्लास में उसको सीमित रक्खा और उसके अकेले वादन के लिए सुविधा नहीं दी। जब वह मर गया तो उसको कमोमोरेट करने के लिए आल इंडिया रेडियो में कोई उसका रेकार्ड प्रोजर्वड नहीं था अलबत्ता जर्मन में जर्मनी ने जिस रेकार्ड को बनाया था ब्रुन्स आफ इंडिया उसको फिर से कहीं से तलाश कर उसको घर से लाकर बजाया गया था। यह है आकाशवाणी में कलाकारों की हालत। सर्दी के जमाने में जब दिल्ली में म्युजिशिएंस लोग आते हैं सवेरे वाद्य यंत्र को बजाने के लिए तो उनके लिए कनवैएंस की भी सुविधा नहीं दी जाती है। सारे आकाशवाणी में स्टाफ कलाकारों की हालत बहुत बुरी है। एक तरफ तो ड्राइवरों, स्टैनोज और चपड़ासियों को भी कुछ सुविधाओं से वंचित करने के लिए स्टाफ आर्टिस्ट्स में शामिल कर लिया और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम उनके लिए कोई बेज बोर्ड नहीं बनायेंगे। मेरी मांग है कि इन कलाकारों को जस्टिस देने के लिए, न्याय देने के लिए आप जल्द से जल्द एक बेज बोर्ड बना दीजिये। इन लोगों के ऊपर आप सरकारी आचरण संहिता लागू करना चाहते हैं लेकिन सरकारी नौकरों को जो सुविधाएं मिलती हैं पैंशन वगैरह की वह नहीं देते हैं। एक रेकार्डिस्ट जो होता है उसकी तनख्वाह 235 रुपये होती थी

[श्री किशन पटनायक]

उसको हटा कर आपने 170 कर दी और उस बेचारे को न जाने क्या क्या काम करने पड़ते हैं ? उसे कोई 17 किस्म के काम करने पड़ते हैं। एक बेज बोर्ड स्टाफ आर्टिस्टों के लिए कायम कीजिये ।

फिर मैं आपका और आपके मंत्रालय का ध्यान कुछ विभागों में यह जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी तरफ भी दिलाऊंगा।

श्रव्य, दृश्य, विज्ञापन और यह प्रचार का जो विभाग है उसके खिलाफ़ कई शिकायतें आप के पास पहुंच चुकी होंगी । इस डिपार्टमेंट में एक क्लर्क है जिसकी कि अपनी फर्म है अपने पिता के नाम से । वह विज्ञापनों को ऐडाप्ट करने का काम करता है । विभाग का कंट्रेक्ट लेता है और अपनी फर्म में काम करवाता है । दूसरा है कोई एक टेकनिकल असिस्टेंट । कोई उस का एक ब्लाक मेकिंग कारखाना है । वह विभाग से कंट्रेक्ट लेकर अपने कारखाने में ब्लाक तैयार करवाता है । इसी तरह जो इस विभाग का अपना स्टुडियो है, स्टुडियो में कलाकार लोग हैं । पता नहीं एक परेश नाथ साहब कहां से आ गये ? यह पिछले दो साल के अन्दर . . .

**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्यों ने इन आदमियों के बारे में सदन में प्रश्न उठाने के लिए लिख कर पूर्व सूचना दी हुई है ?

**श्री किशन पटनायक** : जी हां, लिख कर दे दी है । परेश नाथ साहब को पिछले दो साल के अन्दर करीब एक लाख मिला है ऐसे कामों के लिए जिन कामों के लिए कि विभाग में नौकर रखे गये हैं । विभाग के अन्दर भी इस पर ऐतराज हुआ था लेकिन उस को दबा दिया गया । जिन लोगों ने ऐतराज किया था विभाग के अन्दर उन के खिलाफ़ कार्यवाही हो रही है । आप जांच करवा रहे हैं लेकिन वह जांच किस के द्वारा आप करवा रहे हैं ? जिन अफसरों के खिलाफ़ ऐतराज है, शिकायत है उन्हीं के द्वारा आप यह जांच करवा रहे हैं ।

**श्री भागवत झा आजाद** : धन्य है नौकरशाही ।

**श्री किशन पटनायक** : इस के बारे में कोई एक स्वतंत्र जांच आप करवाइये . . .

**श्री भागवत झा आजाद** : स्वयं कीजिये ।

**श्री किशन पटनायक** : ठीक है जैसा कि श्रद्धेय श्री भागवत झा आजाद ने कहा स्वयं आप यह जांच कीजिये ।

इसी के साथ-साथ कुछ और बातें भी इस डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में मैं कह दूं । यह जो डायरी की बात बेरवा साहब ने की उस को पूरा कर दूं यह कह कर कि विदेशों को आप ने डायरी भेजी हवाई जहाज से और कितना रुपया खर्च करके उन्हें भेजा ? करीब 33, 44 हजार रुपया सिर्फ विदेशों को हवाई जहाज से डायरी भेजने के लिए खर्च किया जा चुका है और विलम्ब होने के कारण जो डायरी बेची नहीं जा सकीं उनकी भी कीमत करीब 40, 50 हजार होगी । इस कारखाने को या कम्पनी को इसलिए दिया गया था कंट्रेक्ट कि उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी दे दूंगा लेकिन उन को दिया गया विलम्ब से । इस के खिलाफ़ सरकार ने क्या कार्यवाही की ? इसके खिलाफ़ सरकार ने यह कार्यवाही की कि इस डायरी के लिए उन को कोई एवार्ड भी दे दिया । उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए सरकार ने उनको प्राइज भी दे दिया ।

ट्रांसमिटिंग स्टेशन के बारे में मैं कह दूं कि ट्रांसमिटिंग स्टेशन कहां कहां होने चाहिए, उस के सम्बन्ध में सारे देश के लिए कोई योजना नहीं है । जब गोपाल रेड्डी साहब मंत्री थे, तो हैदराबाद में एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन बन गया । जब इन्दिरा जी आ गईं, तो इलाहाबाद के लिए भी तय हो गया ।

नन्दिनी जी हैं, तो अच्छा हो कि उड़ीसा में भी एक बन जाये। इस बारे में सारे देश के लिए तो योजना बिल्कुल नहीं है। अब कोई मंत्री आते हैं, तो उन के क्षेत्र में या राजनैतिक प्रेशर के कारण किसी स्थान पर ट्रांसमिटिंग स्टेशन बना दिये जाते हैं।

एक ट्रांसमिटर का एक्विपमेंट दो साल से पड़ा हुआ है, इसलिए कि वह कहां लगाया जाये, इस बारे में कोई राय सही नहीं हो पा रही है। एक बार यह तय हुआ कि वह चंडीगढ़ में लगाया जायेगा। फिर कहा गया कि शिमला में लगाया जायेगा और उस के बाद यह कहा गया कि अलीगढ़ में लगाया जायेगा। पता नहीं, अब उस को कहां लगाने का विचार है।

**श्री क० ना० तिवारी** (बगहा) : नार्थ बिहार में लगा दिया जाये।

**श्री किशन पटनायक** : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सारे हिन्दुस्तान में ट्रांसमिटिंग स्टेशन कहां कहां होने चाहिए, इस के लिए वह कोई योजना बनायें।

इंजीनियरिंग सेक्शन के जो लोग हैं, खर्च करने के बारे में उन को कोई पावर नहीं दी गई है। वे दस रुपये तक खर्च कर सकते हैं और अगर उस से ज्यादा खर्च करना है, तो उन को नौकरशाही के पास जाना पड़ता है, जिससे काम में बहुत देरी होती है।

माननीय मंत्री जी इन बातों को सुधारें।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सामन्त।

**श्री हु० च० सोय** (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा ख़याल है कि आप इस ओर भी देख पायेंगे।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : देख लिया है उन्होंने।

**Shri S. C. Samanta** (Tamluk): Mr. Speaker, Sir, we welcome the new Minister. As has rightly been pointed out by other hon. friends, we should have seen him as a fullfledged Minister of Cabinet rank in the Ministry of Information and Broadcasting. We have according to our Constitution accepted the democratic government in the country; that is, we have taken up party government; one party is elected and for five years they are in charge of the working of the Government. So, the Government has the responsibility to publish what it is doing, for the information of the voters, most of whom are living in villages. So, this Ministry is a very necessary Ministry which would publish the working of the Government in toto. The Ministry of which we are speaking has, to my mind, one good medium of propagating these things which are done by Government. There are other parties who are working in the country and this Government which is working according to its faith also should make its work reach the masses in general so that in future the voters, the people will be able to judge whether they will change the existing Government or not. For that purpose, the Government has the machinery.

Having gone through the report of the Ministry of Information and Broadcasting, I see there is one chapter on field publicity. Field publicity is an organisation which is spread throughout the whole country. Especially during the Pakistani crisis, during the Chinese aggression, this organisation, with its units spread all over the country, worked hard. I had an opportunity to come in contact with the work of this Field Publicity Organisation. My humble self was appointed as Chairman of the Evaluation Committee to assess how they are doing the plan publicity work through non official organisations. The Government has been doing the work; that is all right; but only the Government cannot do it. It cannot reach the remotest corner of the villages. So, if Governmental institutions and

[Shri S. C. Samanta]

non-governmental institutions unite and do the work, then the people will be enlightened; the masses will be enlightened and there will be mass enlightenment, so that the country will prosper more and more.

In my committee's report, we considered that it is the duty of the Government to promote the development of a suitable climate under which non-official participation in national enlightenment can become the effective, self-generating and propelling force. Our findings in this regard is that the existing governmental agencies are extremely inadequate even as a catalytic agent. We recommended that these units should be increased. We felt further that the available potential of non-official collaboration in the country not only remains untouched but has not even been methodically assessed. Properly energised, this could be the cheapest means of mass enlightenment. We were informed that the Central Directorate of Field Publicity have at present got 132 units to cover the entire country. In most of the States, the publicity set-up of the State Governments did not extend below the district level. Besides, the district information officers have varied functions allotted to them and have little time for actual field publicity work. We, therefore, strongly urged that Government agencies of the Centre as well as State Governments should be very substantially strengthened especially in the direction of field publicity.

My hon. friend Shri Sezhiyan was putting before the House that only the Bharat Sevak Samaj was doing that work. (*Interruption*). This aspect of the matter came before us also, and we heard evidence from many organisations which are doing very excellent work in this field. They have different ideas. In our report, we have recommended that more non-official organisations should be asked to participate in the kind of work which the Bharat Sevak Samaj is doing. It was asked why the Bharat Sevak Samaj alone was doing this work and that that organisational alone was getting 90 per cent of the quota that has been allotted for non-official organisations, and that for that reason people are not looking to the good things they are doing. We have given a list in our report and recommended that they should also be asked to participate in the organisation which will help the Government in this work also. I would pay my respects to those friends from the field publicity units who stood by the side of the soldiers in the border areas. They worked wonders. They were fearless and they should be helped and encouraged.

There is a proposal—I hope it is incorrect—that the field publicity units are going to be decreased in number. With the experience I have, I request the government to see that this cut is not made. They are doing good work and I would request the minister to see that our recommendations are implemented. In the report we find that very small things have been accepted and many recommendations have either been rejected or not taken into consideration at all. They merely say that it is under consideration and the State Governments have been asked to look into it. What can the State Governments do? I would again request the minister to look into these things.

**श्री वाल्मीकि** : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी है ।

**श्री भागवत झा आजाद** : ये कहते हैं कि टाइम बढ़ा दिया जाय ।

**Shri A. N. Vidyalankar** (Hoshiarpur): Time should be extended.

**अध्यक्ष महोदय** : जब मिनिस्ट्रीज रह जाती हैं, तो भी शिकायत रहती है ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : आधा घंटा बढ़ा दिया जाय ।

**श्री ह० च० सोय** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । समर्थन करने का कारण यह है कि कुल मिलाकर इस मंत्रालय का काम प्रगति की ओर बढ़ा है और बहुत अच्छा है ।

इस मंत्रालय के फिल्म्ज डिवीजन का काम, जैसा मैंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देखा है, उसकी काफ़ी सराहना की गई है । यह एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में राष्ट्रीय महत्त्व की जो घटनायें घटती हैं, औद्योगिक प्रदर्शिनियां होती हैं, धार्मिक और दूसरे आयोजन होते हैं, वे सारी चीजें डाक्यूमेन्ट्री फिल्म में आ जाती हैं और उस से हमें राष्ट्र की एकता कायम करने में बल मिलता है, भावनात्मक एकता कायम होती है । इस बात के लिये इस मंत्रालय की अवश्य ही तारीफ़ होनी चाहिये । एक ही चीज से हमें बड़ी हैरानी होती है । हमारे फिल्म सेन्सर के स्टेण्डर्ड के अनुसार जहां एक ओर विदेशी फिल्मों में अश्लील से अश्लील बातें आ जाती हैं, अपने देश की फिल्मों में उस चीज को हम सेन्सर कर देते हैं । यह अपनी जगह पर एक अच्छी चीज है, मगर दु-तरफ़ा नीति क्यों अपनाई जा रही है । इसी तरह से हमारे देश के फुट-पाथ पर जो किताबें बिकती हैं, वे बहुत अश्लील होती हैं, हम अपने यहां ऐसी किताबों को क्यों छपने देते हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्रालय इस पर विचार कर के एक समान नीति पर आ जाये और एक ही नीति अपनाये । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और एक निश्चित राय कायम करेंगे ।

एक दूसरी चीज जिसके लिये मैं मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं, वह यह है कि देहाती क्षेत्रों में काफ़ी बड़ी संख्या में रेडियो सेट्स बट रहे हैं, लेकिन अभी भी और ज्यादा रेडियो सेट्स बांटने की जरूरत है, अभी भी हर गांव में एक रेडियो सेट भी नहीं पहुंच सका है । जहां ऐसी परिस्थिति है, वहां हम मंत्री महोदय की ओर से सुन रहे हैं कि टेलीविजन के प्रोग्राम को वे बढ़ाने जा रहे हैं । टेलीविजन के बारे में मेरा भी मत है । हमारे देश में इस वक्त टेलीविजन का समय नहीं आया है । यदि अपने को आधुनिक कहलाने के लिये और बड़े शहरों के कुछ लोगों के मनोरंजन के लिये टेलीविजन लगाया जाता है तो मैं कहूंगा कि यह 90 प्रतिशत लोगों के साथ बड़ा भारी अन्याय होगा । इसलिये मैं टेलीविजन लगाने के सम्बंध में सख्त विरोध करता हूं ।

हां, एक बात यह कही जा सकती है कि अपने देश में यदि टेलीविजन हम बना सकें, इस के बारे में रिसर्च करें, तो बहुत अच्छी बात है । हमारे दोस्त डाक्टर साहब कहते हैं कि पिलानी में एक ऐसा टेलीविजन यंत्र तैयार किया गया है जिस पर आगे चलकर तरक्की की जा सकती है और अगले जमाने में जब टेलीविजन की आवश्यकता होगी, तब लोगों से हम टेलीविजन मैन्यूफैक्चर करा सकते हैं ।

एक चीज के लिये मैं मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं कि हर एक रिजनल केन्द्र में इन लोगों ने एक ट्रांस्मीशन केन्द्र बनाया है । उदाहरण के लिये रांची में बनाया गया है । इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि रांची जैसे केन्द्र को एक शक्तिशाली ट्रांस्मीशन सेन्टर इसलिये बनाया जाय कि उस इलाके में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे दुर्गापुर, राउरकेला और अब बोकारो होगा, रांची में मैं चाहता हूं कि औद्योगिक इलाकों में रहने वालों के लिये रेडियो सुनने के लिये ऐसा इन्तजाम किया जाय कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी जो कार्य हो रहा हो, उनके श्रम सम्बन्धी जो शान्ति और उत्पादन के प्रयत्न होते हों, उसकी खबरें उस रांची सेन्टर से प्रसारित कराई जाय । इसलिये रांची सेन्टर को विशेष शक्तिशाली सेन्टर बनाया जाय और व्यवस्था इस बात की रखी जाय कि औद्योगिक खबरें वहां से प्रसारित हों ।

[श्री ह० च० साय]

एक बात में मैं अन्य मित्रों से सहमत हूं कि रिजनल लैंग्वेज के जो सेन्टर हैं, उसमें अधिक से अधिक हिस्सा रिजनल लैंग्वेज पर खर्च होना चाहिये, लेकिन उसके नाम पर हिन्दी का प्रचार हो, इस सिलसिले में हम यह अवश्य चाहते है कि हिन्दी और अंग्रेजी के लिये जो समय दिया जाता है, वह इस प्रेजेन्ट समय से अधिक न हो ।

एक चीज का मैं विरोध करता हूं । संस्कृत का हमें प्रचार करना है, यह चीज अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन रेडियो से न कर के, दूसरे ढंग से करें ।

**एक माननीय सदस्य :** संस्कृत का विरोध क्यों करते हो ?

**श्री ह० च० साय :** इसका प्रचार दूसरी जगह से करें ।

**श्री बाल्मीकि :** अन्य ढंग से कौन सुनेगा ।

**श्री ह० च० साय :** देहाती क्षेत्रों में हम ने देखा कि जो डाक्यमेन्ट्री फिल्म्ज दिखाई जाती हैं, वे काफी पुरानी होती हैं, जबकि शहरों में जो फिल्में हम देखते हैं, वे लेटेस्ट होती हैं । सरकार ऐसा इन्तजाम क्यों नहीं करती है कि जो डाक्यमेन्ट्री फिल्म्ज शहरों के सिनेमा घरों में दिखाये जाते हैं, वे ही देहाती क्षेत्रों में भी दिखाई जायें । इस में यदि कोई धन की आवश्यकता हो, तो राज्य सरकार के साथ मिल कर देहाती क्षेत्रों में इनके दिखाये जाने का प्रबन्ध किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं बातों को प्रस्तुत करते हुए मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय :** आधे घंटे का समय मिनिस्टर साहब को देना है । सिर्फ 5-5 मिनट ही दिये जा सकते हैं ।

**श्री बाल्मीकि :** मैं 10 मिनट चाहता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं पांच-पांच मिनट वालों को बुला लेता हूं एक तरफ से ।

**Shri S. M. Banerjee:** Sir, while congratulating the staff artistes of the All India Radio on their excellent performance during the emergency and during the Pakistani and Chinese aggression, I wish to make a few comments on the working of the AIR. I am told that the minister, who is new to the ministry, with the help of the new Deputy Minister, is trying his best to improve the service conditions of the staff artistes. Sir, the very name, staff artiste, is a misnomer. From an ordinary peon or chaprasi to the artiste everybody is a staff artiste. I would like to know from the hon. Minister whether any action has been taken on the various recommendations of a particular committee which was appointed to improve the service conditions of the staff artistes. I am told that their contract is being renewed. I have before me a glaring instance of one Shri Brahaspati, recently appointed as Chief Producer of Indian music on a contract for 12 years and 26 days—that is, till his 60th year. The contract can only be terminated on medical grounds. I welcome this. I want that in respect of all the staff artistes who have completed more than ten years of service, who have spent the best portion of their life in serving this country through AIR, their contracts also should be like that and they should be renewed on a similar basis.

My hon. friend, Shri Berwa, mentioned about the Director General. It is a shame on us to think that a particular man—he may be a versatile genuis—who was rejected twice by the UPSC.....

**An hon. Member:** Thrice.

**Shri S. M. Banerjee:** The hon. Member says that he was rejected thrice by the UPSC. It is a hat-trick performed by UPSC. Anyhow, he is still there. I am told that post has been advertised just to suit the convenience of this particular gentleman. I have all respect for Mr. Narayana Menon. He is well up in music and he is generally known as "Ek Thal Menon". But a person who has been rejected thrice is still there. That means the UPSC's decision has no sanctity, no moral sanctity, if he is taken back as Director General.

Now, talking about staff artistes, I must say that they should be given adequate chances of promotion. Men like Shri Shibsagar Misra, who was the first to broadcast about Shastriji's death—it was not broadcast in English, it was Hindi news which gave the entire nation the sad news of Shastriji's death—if there is going to be promotion....

**Mr. Speaker:** He should not take up individual questions.

**Shri S. M. Banerjee:** Sir, he should be congratulated (*Interruptions*). I must congratulate him He is a brave artiste.

**Mr. Speaker:** But when we take up the case of one person, it means we just criticise he others. That would not be for us to do; that should be left to the department.

**Shri Bhagwat Jha Azad:** Sir, may I seek your guidance on one thing? If the Ministry persists in keeping such officers who are rejected by the UPSC not once, not twice but even thrice, should we not mention them and point out.....

**Mr. Speaker:** No, no. We have a rule that if some individual is to be discussed, advance notice has to be given. I allowed Shri Pattnayak only on that condition. (*Interruption*).

**Shri S. M. Banerjee:** Sir, I would request that the organisation of the staff artistes should be recognised, and till it is recognised the Government servants' conduct rules and all other rules should not be made applicable to these employees. Permanency is still awaited. They have not been declared permanent. I want the hon. Minister to take immediate steps to declare them permanent.

They are also clamouring to have a Wage Board. The working journalists in this country, along with all other employees, whether in the public sector or in the private sector, had the advantage either of a Pay Commission or a Wage Board. There should be proper job evaluation and a Wage Board must be given to the staff artistes. All the labour legislations should be implemented in their case also. It is a sad commentary on our democratic functioning that the staff artistes have no channel of negotiation. There is no works committee, no negotiating machinery and no Wage Board for them. Therefore, if you want to improve the lot of the staff artistes, if you want to improve their working conditions, it is necessary that they should be given a Wage Board.

I now come to another assurance which was given in this House, that there will be gratuity and provident fund for the staff artistes. What has happened to that assurance. Ministers are changing every day, and any assurance given by Indiraji or any assurance given by Keskarji should not be kept in cold storage. I know All India Radio has now got a powerful Minister like Shri Raj Bahadur. I am sure he, with the shakti in Satpatiji, will be able to do much in the matter. With these words, Sir, I once again stress that the staff artistes must have their Wage Board and I congratulate the Ministry for their good performance.

**Shri A. N. Vidyalankar:** Sir, I join my other hon. friends in paying my tribute to the hon. Minister, Shri Raj Bahadur, who really deserves the

[Shri A. N. Vidyalankar]

praise showered on him. In fact, I expect, and the House expects, that he will improve matters. I also feel that this is a very important Ministry and it should have been given a place in the Cabinet. It is really unfortunate that this Ministry has been recently down-graded. The Minister in charge of this Ministry should have a place in the Cabinet.

With regard to the publicity that this Ministry is at present arranging, I feel that there is much to be done. At present, speaking as a whole, I feel the publicity that is being done by this Ministry has not been able to make as much impact as we expect, taking into consideration the resources that are being utilised. Very recently so many committees have been appointed. I also had the honour to be the Chairman of a committee. We made certain suggestions. Shri Samanta has referred to the committee on which he was the Chairman. He also referred to certain recommendations. The Chanda Committee report is also there. But the difficulty is that all these recommendations have remained only on paper and the implementation part of it is not done by the Ministry. So far we do not know what are the recommendations that have been accepted by the Ministry and what are the recommendations that are not being accepted, because in the matter of implementation very little has been done. Then, on the question of co-ordination between the mass communication media, the various divisions and others, I think there is very little co-ordination. There is no co-ordination between the various ministries. There was a suggestion that the work of publicity in respect of the various ministries should be co-ordinated through this Ministry. But at present this Ministry is not being taken into confidence properly by the other ministries and each ministry wants to make its own publicity. Therefore, there is no co-ordination and I should say that there is need for such co-ordination.

I should praise the work being done by the Song and Drama Division of the Ministry and also the Films Division. They are doing good work. Recently we have seen certain features, certain dramas that have been organised by the Song and Drama Division. The field publicity division is also doing good work in the border areas. But so far as press publication is concerned there is a lot of scope for improvement. While referring to press publicity I should say that the only press agency PTI that is being supported by the Ministry is not being properly handled It is not placed on a national basis. At present it is in the hands of a few capitalists who are owning the press. Everybody knows that there is no free press in India because practically the press is controlled by certain interests. This agency is being controlled by these interests. Every concern wants that it should make some profit. This agency does not want to make any profit, not because it wants to give certain benefits to its workers, to its employees, but because it wants to give benefit to those press people, those press owners who are owning the press. Therefore, every time they say that they have no capacity to pay more to the workers, with the result that the condition of the workers has remained as it is.

I should also associate myself with what Shri S. M. Banerjee said about staff artistes. The staff artistes are really the persons who should, in any country, be treated with respect and consideration.

But, in our country it is not being done. The position at present is that although they are working whole-time, they are not permanent. Their services can be dispensed with any time. Their appointments are arbitrary. Then, as my hon. friend has pointed out, even drivers, copyists, typists and stenos are included in staff artistes, which is very strange. I hope this mater will receive the personal attention of the Minister.

**16 hrs.**

Then I come to the suggestion made by the Chanda Committee regarding the formation of a corporation. The same suggestion was made by Shri Masani also. He wants that the All India Radio and television should be commercialised. It would be an evil day for India when these agencies are commercialised. I hope the Minister will desist any pressure or temptation to commercialise the All India Radio or television. I do not think it is necessary to form independent corporations to run them. We all know the reason behind this suggestion; I have no time to go into that. I am sure this House will not give support to that suggestion that a corporation should be formed and that it should be taken away from Government for the benefit of private considerations. Even as it is, in India there is no free press. Now, if All India Radio and television are commercialised, in fact if any publicity media is commercialised, the freedom of expression of opinion will be put to an end.

---

**16.01 hrs.**

## CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

HEALTH OF SHRI A. K. GOPALAN—*contd.*

**डा० राम मनोहर लोहिया** (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

> "संसद् सदस्य श्री गोपालन की तन्दुरुस्ती का जेल में बिगड़ना तथा गृह मंत्रालय को उन का तार ।"

**The Minister of Home Affairs (Shri Nanda)**: Mr. Speaker, Sir, at the request of Shri A. K. Gopalan, arrangements were made for his medical check up at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, on the 25th of March 1966. He was earlier examined in this Institute in December 1965. According to the preliminary report of his check up, his general condition appears to be satisfactory. He is known to have suffered from diabetes for about five years. His immediate trouble is reported to be reactivisation of colitis and pain in the teeth. He is to be examined again in the Institute on the 29th March, that is, tomorrow. A medical officer examines him daily. He has examined him today and has found nothing, unusual in his condition.

**Shri A. V. Raghavan** (Badagara): Why do you not release him?

**डा० राम मनोहर लोहिया** : अध्यक्ष महोदय, अपने एक भाई की हालत पर हम लोग विचार कर रहे हैं और इसलिये, अगर आप इजाजत दें तो, एक बूढ़ा रोग, जो अब करीब करीब थक चुका है, उस की जो पुकार मुझ तक आई है, वह मैं आप को सुना दूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, डाक्टर साहब, यह मुनासिब नहीं होगा । अगर आप कोई एल्यूसिडेशन करना चाहें या पूछना चाहें तो वह आप पूछ लीजिये ।

**डा० राम मनोहर लोहिया** : गोपालन जी की हालत अच्छी नहीं है, सब से पहली बात यह है । गृह मंत्री जी से मैं ने यह चाहा था कि मैं उन से अलग से कह दूं और इसलिये उन को टेलीफोन करवाया था और मुझे यह इत्तला दी कि पन्द्रह मिनट के बाद इस के बारे में सूचना आयेगी । शायद कोई झंझट हो गया हो । मैं चाहता था कि मैं उन से इस मामले में एक निजी अपील भी कर दूं कि उन की हालत अच्छी नहीं है

**अध्यक्ष महोदय** : अब आप सवाल पूछिये ।

**डा० राम मनोहर लोहिया** : मेरा सवाल अपील और सवाल दोनों ही हैं आप से